तिब्बत देश

तिब्बत में चीन की तानाशाही दुर्भाग्यपूर्ण

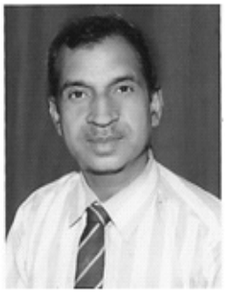

चीन की सरकार द्वारा तिब्बत में की जा रही क्रूरतापूर्ण हिंसा पर रोक के लिए विश्व की मानवतावादी शक्तियों को यथाशीघ्र दबाव बनाना होना। वहाँ हालत इतनी खराब है कि शांतिप्रिय तिब्बती लोग अपने बौद्ध धर्मगुरू परमपावन दलाईलामा की तस्वीर की भी पूजा नहीं कर सकते। चीन सरकार को विश्वास है कि भगवान् बुद्ध के उपदेशों तथा दलाईलामा के प्रवचनों में इतनी ताकत है कि इनसे प्रभावित–प्रेरित–प्रोत्साहित लोगों को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। भगवान् बुद्ध तथा दलाईलामा की वाणी दमन, अत्याचार, हिंसा तथा क्रूरता के शांतिपूर्ण विरोध की वाणी है। वर्ष 2008 की व्यापक जनक्रांति के समय चीन की सरकार तिब्बत में इस तथ्य को अच्छी तरह समझ चुकी है।

चीन की सरकार नहीं चाहती कि तिब्बत संबंधी उसके काले कारनामों की पोल खुले। वहाँ मीडिया पर नियन्त्रण है। देशी–विदेशी मीडिया को चीन सरकार की इच्छा के विपरीत तिब्बत के संबंध में कुछ भी निश्पक्षतापूर्वक तथा निर्भीक होकर प्रकाशित–प्रसारित–प्रचारित करने की छूट नहीं है। तिब्बत के बारे में चीन की सरकार जो बताए, उसी पर पूरा विश्व भरोसा करे। चीन सरकार की यही नीति 1959 से जारी है। तिब्बत पर अवैध कब्जा करने के साथ ही चीन सरकार ने अपनी इस मीडिया विरोधी नीति पर कठोरतापूर्वक अमल शुरू कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप पूरा विश्व तिब्बत से जुड़ी सच्चाई जानने को लगातार बेचैन है।

तिब्बत के मठ–मंदिर व्यापक पैमाने पर चीन की सरकार ने बर्बाद कर दिए। भिक्षु–भिक्षुणियों को मार डाला। धर्मग्रंथ नष्ट कर दिए। पुस्तकालय ध्वस्त कर दिए गए। चीन की सरकार 1959 से लगातार तिब्बत की संस्कृति तथा इसके इतिहास को मटियामेट करने में लगी है। इसी का उदाहरण है कैलाश–मानसरोवर की पवित्र धार्मिक यात्रा पर अंकुश। स्वतंत्र तिब्बत में भारतीय स्वतंत्रापूर्वक कैलाश की तथा मानसरोवर की यात्रायें करते रहते थे। खर्चा भी मामूली होता था। इस यात्रा से तिब्बत एवं भारत के सांस्कृतिक–आध्यात्मिक संबंध मजबूत होते रहते थे। अब उन पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए भारतीयों को चीन सरकार से अनुमति लेनी होती है। इस अनुमति के बदले चीन सरकार हजारों रूपये वसूलती है। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों पर खुफिया नजर रखी जाती है। दुर्गम तथा प्राकृतिक आपदाओं से भरपूर पर्वतीय–बर्फीले मार्ग में भी तीर्थयात्रियों को चीनी प्रशासन के कटु व्यवहार को झेलना होता है। कैलाश–मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्री प्रकृति के प्रकोप की तुलना में वहाँ के प्रशासन से ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। इस प्रकार तिब्बत के भारत के साथ चले आ रहे हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संबंधों को कमजोर करने का अक्षम्य अपराधी है चीन।

तिब्बत में अघोशित चीनी तानाशाही का परिणाम है कि तिब्बती अपने ही देश में आत्महत्यायें कर रहे हैं। आत्मदाह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें रूकने का नाम नहीं ले रहीं। कुछ साल पहले उम्मीद जगी थी कि चीन का नया नेतृत्व दलाईलामा के साथ सार्थक संवाद कायम करके समस्या का हल निकालेगा। लेकिन हु जिंताओ तथा बेन जिआ बाओ के तथाकथित नए नेतृत्व ने तिब्बत में पहले से जारी दमनकारी नीति को ही जारी रखा। अब फिर से चीन में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोरों पर है। लेकिन स्थिति बदलने वाली नहीं लगती। चीन की कमान जिन नेताओं के हाथ होगी, वे भी अपने पूर्ववर्ती नेताओं के समान ही तिब्बत में क्रूरतापूर्ण विनाशकारी नीति जारी रखेंगे। उनकी मानसिक–बौद्धिक स्थिति अपने पूर्ववर्ती नेताओं जैसी ही है। इसलिए चीन के नए नेतृत्व से तिब्बत के संबंध में बदलाव की उम्मीद से बेहतर है कि वहाँ के वर्तमान नेतृत्व को ही दलाईलामा के साथ सार्थक संवाद बनाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जायें। तिब्बत यदि चीन का अपना होता, तो कभी भी चीन वहाँ हिंसापूर्ण कर्रवाई नहीं करता। वहाँ के पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र तथा सामाजिक संरचना को नुकसान नहीं पहुँचाता। चीन को पता है कि तिब्बत स्वतंत्र होकर रहेगा, इसलिए वह तिब्बत में ही तिब्बतियों को अल्पसंख्यक बनाने में जुटा है। वहाँ के सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में निर्णयात्मक पदों पर तथा विभिन्न कार्यक्रमों के शीर्श पदों पर चीन के लोग बैठा दिए गये हैं। क्या कोई भी देश अपने ही क्षेत्र में तथा अपने ही लोगों के विरूद्व ऐसी साजिश रचेगा? तिब्बत में जो भी निर्माण–कार्य और विकास–कार्य नजर आ रहे है उनका उद्देश्य तिब्बत एवं तिब्बतियों का कल्याण नहीं है। वे चीन के तिब्बत विरोधी साजिशपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता।

अभी तिब्बत समर्थक संगठनों एवं व्यक्तियों को तिब्बत के अंदर और बाहर बढ़ रही तिब्बतियों के आत्मदाह की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु कारगर कदम उठाने होंगे। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का एक उद्देश्य है चीन की क्रूरतापूर्ण अमानवीय तिब्बत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ विश्वस्तरीय जनमत का निर्माण करना। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत की नाजुक स्थिति को समझा जाए, तो आत्मदाह की घटनायें अपने आप रूक जायेंगी। इस हेतु जरूरी है कि मानवाधिकारवादी तथा मीडिया से जुड़े लोग निरंतर तिब्बत के दौरे करें एवं चीन की अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करते रहें। चीन सरकार तिब्बत के अंदर इन्हें कार्य करने की पूरी छूट दे। यह चीन की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वहा संयुक्त राष्ट्र संघ का अतिमहत्वपूर्ण सदस्य है। उसे अपनी साम्राज्यवादी–उपनिवेशवादी नीति को छोड़ना होगा। साथ ही तिब्बत की आजादी हेतु लड़ने वाले तिब्बती भी आत्मदाह जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से स्वयं को बचायें, तो बेहतर होगा। तिब्बत को आज मरने वालों से ज्यादा तिब्बत के लिए जीने वाले स्वतंत्रासेनानियों की आवश्यकता है।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र

पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)

अब एक किशोर तिब्बती ने विरोधस्वरूप किया आत्मदाह

पूर्वी तिब्बत के नाबा काउंटी स्थित सैन्य शिविर के पीछे शनिवार 10 मार्च को आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने वाले कीर्ति मठ के 18 साल के भिक्षु की मौत हो गई है।नाबा को चीनी प्रशासन के लिहाज से अबा काउंटी कहते हैं और यह सिचुआन प्रांत के अबा स्वायत्तशासी प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित है।

(एनडीटीवी डॉट कॉम, 6 मार्च, चीन) पिछले तीन दिन में चीन में विरोध प्रदर्शन के चरम कदम के तहत खुद को आग लगाने से तीसरे तिब्बती की मौत हो गई है। आंदोलनकारी संगठन 'फ्री तिब्बत' ने सोमवार को खबर दी है कि आत्मदाह करने वाले 18 साल के दोरजी की सिचुआन प्रांत के अबा काउंटी में स्थित एक सरकारी इमारत के भीतर मौत हो गई है। उन्होंने इमारत के बाहर खुद को आग लगा लिया और आग की लपटों के साथ ही दौड़ते हुए अंदर जाने की कोशिश करने लगे। कुछ ही छण में वह गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। कई अन्य तिब्बती संगठनों एवं निर्वासित तिब्बती सरकार ने भी इस घटना की पुष्टि की है। फरवरी, 2009 के बाद से ही विरोधस्वरूप आत्मदाह कर मौत को गले लगा लेने वाले दोरजी 26वें तिब्बती हैं। उनकी मौत के दिन ही सोमवार को संयोग से धर्मशाला में एक विरोध मार्च का आयोजन किया गया था। निर्वासित तिब्बती, भिक्षु और आंदोलनकारी जुटकर चीन द्वारा तिब्बती संस्कृति एवं धर्म के दमन की निंदा कर रहे थे जिसे कि वह आत्मदाह की लहर शुरू हो जाने की वजह मानते हैं। फ्री तिब्बत की निदेशक स्टीफैनी ब्रिगदेन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है। संगठन की वेबसाइट पर जारी बयान में उन्होंने कहा है, "कुछ ही दिनों में इस तीसरे आत्मदाह से इस बात को बल मिलता है कि तिब्बती तब तक विरोध करना जारी रखेंगे जब तक आज़ादी की उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस बारे में तत्काल कार्रवाई करना चाहिए।" चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल में विरोध प्रदर्शनों के सिलसिल को देखते हुए उत्तर–पूर्वी चीन के तिब्बती इलाकों में अपने नियंत्रण को और सख्त कर दिया है। आत्मदाह का सिलसिला अब भी जारी है और पिछले हफ्ते इसी तरह की दो अलग घटनाओं में दो औरतों ने अपनी जान दे दी है।

अशांत नाबा में आत्मदाह करने से तिब्बती महिला की मौत

(वीओए, 4 मार्च, 2012) पूर्वी तिब्बत के नाबा काउंटी (चीनी में अबा काउंटी) में रविवार को सुबह आत्मदाह कर लेने से एक तिब्बती महिला की मौत हो गई है। भारत स्थित कीर्ति मठ से जुड़े वेन. लोबसांग येशी ने वीओए की तिब्बती सेवा को बताया कि चार बच्चों की मां 33 साल की रिनछेन ने सुरक्षा बलों के मजबूत घेरे वाले कीर्ति मठ के बाहर बने विशेष सुरक्षा कार्यालय के सामने ही खुद को आग लगा ली। इस मठ के कई भिक्षुओं के आत्मदाह कर लेने के बाद से ही यहां भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। खबरों के अनुसार आग की लपटों में घिर जाने से पहले रिनछेन ने तिब्बत में आज़ादी बहाल करने और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की वापसी के नारे लगाए। ब्रिटेन स्थित आज़ादी समर्थक संगठन फ्री तिब्बत ने बताया कि रिनछेन अपने पीछे चार बच्चे छोड़ गई हैं इनमें सबसे बड़ा 13 साल का और सबसे छोटा सिर्फ कुछ माह का ही। उनके पति की भी एक साल पहले मौत हो गई थी। फ्री तिब्बत ने बताया कि रिनछेन अपने घुमंतू इलाके से नाबा सिर्फ आत्मदाह करने के इरादे से आई थीं। यह आत्मदाह की घटना ऐसे समय में हुई है जब 14 मार्च को साल 2008 में तिब्बत में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों की वर्षगांठ आने वाली है। चीन ने 16 मार्च, 2011 को कीर्ति मठ के युवा भिक्षु फुंसोग के आत्मदाह कर लेने के बाद नाबा के तिब्बती इलाके में कार्रवाई तेज कर दी है। तबसे अब तक 15 से ज्यादा तिब्बतियों ने नाबा इलाके में आत्मदाह कर लिया है। हाल में हुई आत्मदाह की घटनाएं चीन के शासन के विरोध की रणनीति में भारी बदलाव का संकेत देती हैं और चीन सरकार इन कार्यों की कटु आलोचना कर रही है। पिछले एक साल में चीनी शासन की खिलाफत करते हुए 20 से ज्यादा तिब्बती खुद को आग लगा चुके हैं। निर्वासित तिब्बती नेतृत्व और आंदोलनकारी संगठनों ने आशंका जाहिर की है कि आगे तिब्बत में और आत्मदाह की घटनाएं एवं खूनखराबा हो सकता है क्योंकि हाल के हफ्तों में तिब्बत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को चीन सरकार ने हिंसक रूप से कुचला है। चीन सरकार ने आत्मदाह की घटनाओं की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद का ही एक रूप बताया है। चीन ने यह भी आरोप लगाया है कि तिब्बतियों के निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ऐसी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं। दलाई लामा ने आत्मदाह को प्रोत्साहित करने की बात से इनकार किया है। साल 2010 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में 76 साल के बौद्ध नेता दलाई लामा ने कहा है कि जिन लोगों ने आत्मदाह किया वे बहादुर थे, लेकिन उनका यह बलिदान बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं है क्योंकि इससे चीनी प्रशासन का दमन और कठोर हो गया है।

आत्मदाह की लहर में अब एक तिब्बती स्कूली छात्रा की मौत

(वीओए, 5 मार्च, 2012) शनिवार को गन्नान तिब्बती स्वायत्तशासी प्रशासनिक क्षेत्र के माछू काउंटी में आत्मदाह कर लेने से एक 19 वर्षीय तिब्बती छात्रा की मौत हो गई है। तिब्बत के भीतर के एक सूत्र ने वायस ऑफ अमेरिका को बताया कि आत्मदाह करने वाली छात्रा सेरिंग की पढ़ाई में अच्छी थी और उसका परिवार इसी काउंटी के एक कस्बे मेनमा का रहने वाला था। सेरिंग करीब 3 बजे दोपहर में मेनमा कस्बे गईं और उसने वहां बाजार से पेट्रोल खरीदा। उन्होंने एक सार्वजनिक शौचालय के भीतर खुद को आग लगाया और आग की लपटों के साथ ही एक चीन संचालित सब्जी बाजार की ओर दौड़ पड़ीं। खबरों के अनुसार इसके बाद सुरक्षा पुलिस सेरिंग के शव को उठाकर ले गई और उनके परिवार को शव सौंपने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन स्थित संगठन फ्री तिब्बत लिखता है कि इस घटना से कुछ दिन पहले ही सेरिंग की ने कहा था, "नाबा और तिब्बत के अन्य इलाकों में तिब्बती लोग खुद को जला रहे हैं। हमें कुछ करना चाहिए। यदि हमने तिब्बत के लिए कुछ नहीं किया तो हमारा जीवन निरर्थक होगा।" भारत स्थित निर्वासित तिब्बती संसद ने एक बयान जारी कर कहा है

कि विरोध प्रदर्शन की घटना के तुरंत बाद वहां चीनी सुरक्षाकर्मी पहुंच गए और उन्होंने पूरे बाजार को बंद करा दिया। संसद के बयान में कहा गया है, "इस विरोध प्रदर्शन की खबर को फैलने से रोकने के लिए सभी लोगों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को इस आत्मदाह के बारे में कुछ भी बोलने के खिलाफ सख्त हिदायत दी गई।" तिब्बत के एक पूर्व राजनीतिक कैदी डोलकर क्याप (जो अब भारत में रहते हैं) ने कहा कि सेरिंग की एक घुमंतू किसान परिवार से थीं और उनकी एक बड़ी बहन हैं। क्याप ने वीओए को बताया कि इस आत्मदाह के बाद काउंटी में एक आपात बैठक बुलाई गई और प्रशासन के लोगों ने यह तय किया कि इस आत्मदाह की घटना को व्यक्तिगत वजहों एवं प्रेम प्रसंग से जुड़ा मसला बताकर प्रचारित किया जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सोमवार को सभी स्कूलों एवं बाजारों को बंद रखा जाए।

मार्च, 2011 से ही अब तक 25 तिब्बती दलाई लामा को निर्वासन से वापस तिब्बत लाने और तिब्बत में आज़ादी की बहाली की मांग को लेकर खुद को आग लगा चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों में समूचे तिब्बती पठार के सभी तिब्बती क्षेत्रों में सख्ती और मनमाने तरीके से लोगों को पीटने एवं गिरफ्तार करने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। शायद यह संभावित विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए उठाया गया कदम हो क्योंकि मार्च में साल 2008 एवं 1959 के तिब्बती जनक्रांति की वर्षगांठ वाले संवेदनशील दिन करीब हैं।

तिब्बती जनक्रांति दिवस पर 18 साल के भिक्षु ने आत्मदाह किया

(वीओए, 12 मार्च) पूर्वी तिब्बत के नाबा काउंटी स्थित सैन्य शिविर के पीछे शनिवार 10 मार्च को आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने वाले कीर्ति मठ के 18 साल के भिक्षु की मौत हो गई है। नाबा को चीनी प्रशासन के लिहाज से अबा काउंटी कहते हैं और यह सिचुआन प्रांत के अबा स्वायत्तशासी प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित है।ब्रिटेन स्थित संगठन फ्री तिब्बत ने बताया कि इस घटना के तुरंत बाद चीनी अधिकारी गेपे नाम के इस भिक्षु के शव को उठा ले गए और उसी रात उनका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। भारत स्थित कीर्ति मठ के प्रवक्ता लोबसांग येशी ने वीओए को बताया गेपे अपने पीछे अपनी मां और दो भाइयों को छोड़ गए हैं। उनके दोनों भाई भी कीर्ति मठ में भिक्षु हैं। आत्मदाह की यह नवीनतम घटना ऐसे संवेदनशील समय में हुई है जब 10 मार्च को 1959 के तिब्बती जनक्रांति और मार्च 2008 के चीन विरोधी तिब्बतव्यापी प्रदर्शनों की वर्षगांठ है। तिब्बत में चीनी शासन के विरोध में तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर हजारों निर्वासित तिब्बती सड़कों पर उतर आए। पिछले साल 16 मार्च को कीर्ति मठ के युवा भिक्षु फुंसोग की आत्मदाह से मौत होने के बाद चीन ने नाबा के तिब्बती इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। निर्वासन में स्थित कीर्ति मठ के एक भिक्षु ने बताया कि फुंसोग के आत्मदाह और इसके बाद कीर्ति मठ के भिक्षुओं द्वारा दिखाई जाने वाली एकजुटता के बाद चीनी प्रशासन ने कीर्ति मठ में कठोर देशभक्ति शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। अप्रैल, 2011 में चीनी प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कीर्ति मठ के 300 से भी ज्यादा भिक्षुओं को हिरासत में ले लिया। कीर्ति मठ इस इलाके के सबसे प्रमुख धार्मिक संस्थाओं में से है। इन भिक्षुओं के गायब हो जाने के बाद चीनी प्रशासन इसमें अपना हाथ होने से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में उसने यह स्वीकार किया कि इन भिक्षुओं को जबरन एक अज्ञात स्थान पर 'कानूनी शिक्षा' हासिल करने के लिए भेजा गया है। मार्च, 2011 से ही अशांत नाबा क्षेत्र में 16 से ज्यादा तिब्बतियों के आत्मदाह कर लेने की खबरें हैं। समूचे तिब्बत में पिछले साल मार्च से अब तक कम से कम 25 भिक्षुओं, भिक्षुणियों और अन्य लोगों ने दलाई लामा को निर्वासन से वापस बुलाने और तिब्बत में आज़ादी की मांग को लेकर आत्मदाह कर लिया है। फिलहाल नाबा क्षेत्र में स्थिति काफी तनावपूर्ण है क्योंकि चीन ने वहां सख्त कार्रवाई, लोगों को मनमाने तरीसे गिरफ्तार करने और उनकी पिटाई करने की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पिछले बुधवार को चीनी प्रशासन ने कहा कि आत्मदाह की बढ़ती लहर की वजह से तिब्बती इलाका काफी हद तक अस्थिर है, हालांकि इस आग के ठंडे पड़ने के कुछ लक्षण दिखे हैं। निर्वासित तिब्बती नेतृत्व और आंदोलनकारी संगठनों ने तिब्बत में और भी आत्मदाह तथा खून–खराबे की आशंका जताई है क्योंकि हाल के हफ्तों में तिब्बत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का चीनी प्रशासन द्वारा दमन काफी बढ़ गया है। निर्वासित तिब्बत सरकार के नेता ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वे तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों की मदद के लिए हस्तक्षेप करें।

तब्बत से आती खबरों से पता चला है कि तिब्बत में चीन सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दो और तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है।

चीन में विरोध प्रदर्शत के तहत एक और तिब्बती ने आत्मदाह किया

(वीओए, 17 मार्च) पूर्वी तिब्बत के नाबा काउंटी में 16 मार्च को सायं करीब 5 बजे एक 20 साल के तिब्बती भिक्षु ने आत्मदाह कर लिया। भारत स्थित कीर्ति मठ के प्रवक्ता ने बताया कि अशांत कीर्ति मठ से जुड़े लोबसांग सुलत्रिम नाम के ये भिक्षु आग की लपटों में ही सड़क पर दौड़ते रहे और उन्होंने तिब्बत में चीन की दमनकारी नीतियों के विरोध में नारे लगाए। खबरों के अनुसार चीनी सुरक्षा बलों ने आग की लपटों को बुझाने का प्रयास जरूर किया लेकिन वह सुलत्रिम की पिटाई भी करते रहे। यह भिक्षु कहां हैं और उनकी मौजूदा हालत क्या है इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। सूत्रों के अनुसार जब सुरक्षा बल सुलत्रिम को एक वाहन में रखकर अज्ञात स्थान की ओर ले जा रहे थे, तब तक तो वे जिंदा थे। सूत्रों के अनुसार सुलत्रिम सिर्फ आठ वर्ष की अवस्था में ही कीर्ति मठ में शामिल हो गए थे और वह अपने चार भाई–बहनों में सबसे बड़े हैं।

अप्रैल, 2011 में चीनी अधिकारियों ने कीर्ति मठ से 300 से ज्यादा भिक्षुओं को गिरफ्तार किया था।

नाबा में सख्त कार्रवाई

खबरों के अनुसार शुक्रवार सुबह से ही कीर्ति मठ के मुख्य द्वार के पास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। मठ के आसपास पहले से ही भारी संख्या में सैन्य बल तैनात थे

दलाई लामा ने उन लोगों के साहस की तारीफ की है जिन्होंने आत्मदाह किया है और तिब्बत में चीन के कथित 'सांस्कृतिक नरसंहार' के विरोध में अपना योगदान दिया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि वे इस तरह के विरोध प्रदर्शन को प्रोत्साहित नहीं करते क्योंकि इनका सख्ती से दमन किया जा सकता है।

और अब यह संख्या और बढ़ गई है। पिछले साल 16 मार्च को कीर्ति मठ के युवा भिक्षु फुंसोग के आत्मदाह कर लेने के बाद से ही चीन ने नाबा के आसपास के तिब्बती इलाकों में कड़ी कार्रवाई की है। निर्वासन में स्थिति कीर्ति मठ के भिक्षुओं ने बताया कि फुंसोग के विरोध प्रदर्शन और इसके बाद कीर्ति मठ के भिक्षुओं द्वारा दिखाई गई एकजुटता को देखते हुए चीनी प्रशासन ने कीर्ति मठ में कठोर देशभक्ति शिक्षा अभियान शुरू किए हैं। अप्रैल, 2011 में चीनी अधिकारियों ने कीर्ति मठ से 300 से ज्यादा भिक्षुओं को गिरफ्तार किया था। कीर्ति मठ इस इलाके के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाओं में से एक है। पहले तो चीनी प्रशासन इन गायब हुए 300 भिक्षुओं की गिरफ्तारी से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में उसने यह स्वीकार किया कि इन भिक्षुओं को जबरन 'कानूनी शिक्षा' में शामिल करने के लिए अज्ञात स्थान पर भेजा गया है। फिलहाल नाबा क्षेत्र में स्थिति काफी तनावपूर्ण है क्योंकि चीन ने अपनी कार्रवाई और कड़ी कर दी है। नाबा में लोगों को मनमाने तरीके से पीटा जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।

आत्मदाह की लहर

मार्च, 2011 के बाद से ही अकेले नाबा इलाके में 17 से ज्यादा तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। यही नहीं, तिब्बत में आज़ादी बहाल करने और परमपावन दलाई लामा को वापस बुलाने की मांग को लेकर समूचे तिब्बत में मार्च, 2011 से अब तक कम से कम 28 भिक्षु, भिक्षुणी और अन्य लोग आत्मदाह कर चुके हैं। बुधवार, 14 मार्च, 2012 को क्विंघई प्रांत के आमदो इलाके में 38 साल के भिक्षु रेबकांग ने आत्मदाह कर लिया। पिछले शनिवार को कीर्ति मठ के एक और भिक्षु ने आत्मदाह कर लिया था। 10 मार्च का यह दिन काफी संवदेनशील है क्योंकि इसी दिन 1959 में विफल रही तिब्बती जनक्रांति और मार्च, 2008 में चीनी शासन के खिलाफ समूचे तिब्बत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की वर्षगांठ होती है।

इस हफ्ते चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने कहा कि तिब्बत में हो रही आत्मदाह की घटनाओं से वह 'काफी व्यथित' हैं। वेन ने आरोप लगाया कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार चीन के सामाजिक सौहार्द को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1959 से ही भारत में निर्वासन में रह रहे दलाई लामा ने उन लोगों के साहस की प्रशंसा की है जिन्होंने आत्मदाह किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसे कभी प्रोत्साहित नहीं करते और न ही यह सोचते हैं कि इससे चीनी नेताओं पर कोई असर पड़ने वाला है। दलाई लामा और तिब्बतियों के निर्वाचित नेता लोबसांग सांगे, दोनों का यह आरोप है कि आत्मदाह का जो सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा उसकी वजह चीन द्वारा तिब्बती धर्म और संस्कृति का दमन ही है। निर्वासित तिब्बती नेतृत्व और आंदोलनकारी संगठनों ने आगे और भी आत्मदाह एवं खून–खराबे की आशंका जाहिर की है क्योंकि हाल के हफ्तों में तिब्बत में चीनी प्रशासन ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का काफी हिंसक तरीके से दमन किया है। निर्वासित तिब्बत सरकार के नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि वे तिब्बत के भीतर रहने वाले लोगों की भलाई के लिए हस्तक्षेप करें।

तिब्बत में दो और तिब्बतियों ने किया आत्मदाह

(तिब्बत डॉट नेट, 31 मार्च, धर्मशाला) तिब्बत से आती खबरों से पता चला है कि तिब्बत में चीन सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दो और तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। बरखाम में गत 30 मार्च को प्रशासनिक सरकारी कार्यालय के बाहर दो तिब्बतियों 22 साल के तेनपा डार्गे और 21 साल के छिमे पालदेन ने खुद को आग लगा लिया। ये दोनों ग्यालरोंग स्थित सोदुन कीर्ति मठ के भिक्षु थे। दोनों भिक्षु बरखाम के सोदुन कस्बे के खोलाछांग गांव के निवासी हैं। दोनों भिक्षुओं को इस घटना के तत्काल बाद सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। घटना की खबर मिलते ही सोदुन मठ के भिक्षु तुरंत बरखाम की ओर भाग पड़े ताकि दोनों भिक्षुओं को अपने पास रखा जाए। लेकिन मठ से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जेतो नामक स्थान पर सशस्त्र सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया और वापस मठ में जाने का आदेश दिया। अभी दोनों भिक्षुओं की हालत कैसी है इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। चीन सरकार ने प्रशासनिक सरकारी मुख्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बंदोबस्त कर दिए हैं और बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। आत्मदाह करने वाले एक भिक्षु तेनपा देर्गे ने नाबा के कीर्ति मठ में साल 2003 से 2009 तक दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की थी। सोदुन मठ में पढ़ाई के दौरान उन्हें तार्किक वाद–विवाद कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से माना जाता था। वह अपने चार भाई–बहनों में से सबसे छोटे थे। इसी प्रकार छिमे पालदेन साल 2009 में दर्शन के छात्र के रूप में कीर्ति मठ पहुंचे थे, लेकिन वह वहां कुछ ही महीने रहे। साल 2010 में जब वह ल्हासा की यात्रा पर गए थे तो जन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से उन्हें हिरासत में लिया क्योंकि उनके पास दलाई लामा की तस्वीर, एक तिब्बती राष्ट्रीय झंडा और उनके मोबाइल में राष्ट्रीय गीत था। सोदुन कीर्ति मठ बरखाम कस्बे से करीब 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मठ का औपचारिक नाम गांदेन टाशी छोलिंग है। इस मठ में फिलहाल करीब 300 भिक्षु हैं। यह ग्यालरोंग के सबसे बड़े गेलुग्पा मठों में से एक है। साल 2009 से अब तक 34 तिब्बतियों ने आज़ादी और परमपावन दलाई लामा को वापस बुलाने की मांग करते हुए आत्मदाह किया है। इनमें से 23 लोग शहीद हो चुके हैं और दूसरे लोगों की या तो हालत गंभीर है या उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। तिब्बत के हालात पर गहरी चिंता जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने बुधवार को कहा, "हमें तिब्बती इलाकों में तनाव और मानवाधिकारों को लेकर गहरी चिंता है।" न्यूलैंड ने कहा, "चीन द्वारा लगातार दलाई लामा की मानहानि और उनके ऊपर बार–बार आरोप लगाना और यह कहना कि वह इन घटनाओं में सीधे शामिल हैं, इससे तिब्बतियों का असंतोष और बढ़ा रहा है तथा स्थिति और गंभीर होती जा रही है। इसलिए हम चीन से अनुरोध करते

हैं कि तिब्बतियों के मानवाधिकारों का सम्मान करे और वहां पत्रकारों को जाने की इजाजत दे।"

तिब्बत में इंटरनेट, मोबाइल फोन पर पाबंदी और सख्त

(पीटीआई, 1 मार्च, बीजिंग) चीन ने बौद्ध भिक्षुओं में आत्मदाह की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए तिब्बत में मोबाइल फोन एवं इंटरनेट पर सख्ती और बढ़ा दी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि इस संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में स्थिरता कायम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। तिब्बत डेली में छपे बयान में तिब्बत में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख छेन क्वांगुओ ने कहा, "मोबाइल फोन, इंटरनेट और नए मीडिया के प्रबंधन के लिए अन्य सभी उपायों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा।" उन्होंने अधिकारियों से यह संदेश भी फैलाने को कहा कि तिब्बत में स्थिरता सबसे जरूरी है और "अस्थिरता फैलाने वाले तत्वों को विकसित होने से पहले ही कुचल दिया जाए।" दूसरी तरफ, चीन के एक शीर्ष नेता जिया क्विंगलिन ने इस बात पर जोर दिया है कि तिब्बत और सिचुआन, युन्नान, गांसू एवं क्विंघई प्रांत के तिब्बती बस्तियों वाले इलाकों में लगातार एवं तेज आर्थिक विकास को बनाए रखा जाए और सामाजिक सहिष्णुता एवं स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया जाए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य जिया ने कहा कि तिब्बत में स्थिरता की चिंता ऐसे दौर में और भी मायने रखती है क्योंकि सीपीसी इस साल देश का नया नेता चुनने के लिए 18वीं पार्टी कांग्रेस का आयोजन करने जा रही है। जिया ने अधिकारियों से कहा कि वे तिब्बत और चार प्रांतों के तिब्बती बाशिंदों वाले इलाकों में काम को अच्छे तरीके से करें क्योंकि ये पार्टी और देश दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के मुताबिक जिया ने कहा, "हमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह की स्थितियों पर विचार करना चाहिए और मजबूती से 'स्थिरता बनाए रखते हुए प्रगति करने' के भाव को समझना चाहिए, तिब्बत एवं तिब्बती आबादी वाले चारों प्रांतों में लगातार आर्थिक प्रगति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।" उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन ने समूचे तिब्बत और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत में निर्वासन में रह रहे दलाई लामा को वापस बुलाने की मांग करते हुए इन इलाकों में हाल में बौद्ध भिक्षुओं के आत्मदाह की घटनाएं बढ़ी हैं। अब तक करीब 22 भिक्षु और भिक्षुणियां आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है।

चीन ने तिब्बत में आत्मदाह करने वालों को अपराधी, बहिश्कृत बताया

(एसोसिएटेड प्रेस, 7 मार्च, बीजिंग) चीनी अधिकारियों ने बुधवार को उन तिब्बती लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जिन्होंने अपने इलाके में चीनी शासन के खिलाफ आत्मदाह कर लिया है। चीनी अधिकारियों ने इन लोगों के बारे में कहा कि वे अपराधी, बहिष्कृत और मानसिक रूप से बीमार ऐसे लोग हैं जो निर्वासित दलाई लामा द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तिब्बती बौद्ध आध्यात्मिक नेता ने कहा है कि वह आत्मदाह को प्रोत्साहित नहीं करते, लेकिन चीनी अधिकारी यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि करीब दो दर्जन लोगों के आत्मदाह की पिछले साल शुरू हुई लहर (जिसमें पिछले शनिवार से अब तक तीन आत्मदाह की घटनाएं भी शामिल हैं) में बाहरी लोगों का हाथ है, जबकि तिब्बती आंदोलनकारियों का कहना है कि चीन सरकार द्वारा तिब्बती धर्म एवं संस्कृति के दमन की वजह से स्थानीय लोगों में जो असंतोष बढ़ा है यह उसी का नतीजा हैं।

विरोध प्रदर्शन करने वाले बहुत से लोग सिचुआन प्रांत के पहाड़ी इलाके अबा प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित एक बौद्ध मठ से जुड़े हैं। अबा में चीन सरकार के शीर्ष प्रशासक तिब्बती नस्ल के वु जेगांग ने कहा, "आत्महत्या की कुछ घटनाएं ऐसे भिक्षुओं द्वारा की गई हैं जो सामान्य जीवन में लौट चुके हैं और ये सब संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।"वु ने बीजिंग में पत्रकारों को बताया कि आत्मदाह की घटनाएं दलाई लामा एवं तिब्बत की आज़ादी की मांग करने वाली ताकतों द्वारा 'नियोजित और समर्थित हैं।' उन्होंने कहा कि खुद को आग लगाने से पहले आत्मदाह करने वालों ने 'तिब्बत की आज़ादी की मांग या अन्य ऐसे नारे लगाए हैं जिनका उद्देश्य देश का बांटना है।'

दलाई लामा ने उन लोगों के साहस की तारीफ की है जिन्होंने आत्मदाह किया है और तिब्बत में चीन के कथित 'सांस्कृतिक नरसंहार' के विरोध में अपना योगदान दिया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि वे इस तरह के विरोध प्रदर्शन को प्रोत्साहित नहीं करते क्योंकि इनका सख्ती से दमन किया जा सकता है। बीजिंग में बुधवार को आयोजित नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में तिब्बती प्रतिनिधियों की बैठक के बाद जब एक पत्रकार ने कुछ वेबसाइट पर कथित रूप से लोगों की मांग का हवाला देते हुए पूछा कि क्या तिब्बती नेता यह सोचते हैं दलाई लामा को खुद आत्मदाह करना चाहिए, तो इस पर तिब्बत के गवर्नर पदमा छोलिंग ने कहा कि उनका मानना है कि किसी को भी खुद को आग नहीं लगाना चाहिए। पदमा ने कहा, "यह बात मायने नहीं रखती कि कौन आत्मदाह करता है, यह एक अमानवीय और अनैतिक कार्य है। यदि दलाई लामा आत्मदाह करते हैं तो यह उनका अपना निर्णय होगा और इससे मेरा कोई लेना–देना नहीं है। लेकिन यह कोई भी करे मैं इसकी वकालत नहीं करता। जीवन अनमोल है। मैं यह तो उम्मीद नहीं करूंगा कि कोई आत्मदाह करे।"गौरतलब है कि अबा में आत्मदाह की सबसे हालिया घटना कुछ दिनों पहले ही हुई है। चार बच्चों की मां 32 साल की एक महिला ने शनिवार को अबा में खुद को आग लगाकर जान दे दी। इसी प्रकार इंटरनेशनल कमिटी फॉर तिब्बत एवं अमेरिकी रेडियो फ्री एशिया की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 18 साल के दोरजी ने आत्मदाह कर जान दे दी। सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने इस बात की पुष्टि की है कि शनिवार को पड़ोसी गांसू प्रांत में एक और महिला ने आत्मदाह किया है, लेकिन एजेंसी का

"हमें उम्मीद है कि चीन के आगामी नेता वास्तविक बदलाव की शुरुआत करेंगे और वे यह स्वीकार करने की बुद्धिमत्ता दिखाएंगे कि तिब्बत में चीन सरकार की कठोर नीतियां विफल हो चुकी हैं।" सांगे का यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब दुनिया भर में तिब्बती 'जनक्रांति दिवस' मना रहे हैं।

एशिया–प्रशांत के मंच पर अमेरिकी नौसैनिकों की भारी तैनाती बने रहना, जापानी नौसैनिकों की ज्यादा सक्रिय और सबल मौजूदगी और इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया एवं वियतनाम जैसे प्रमुख समुद्र तटवर्ती देशों द्वारा नौसैन्य क्षमता का विकास, इन सबसे हिंद महासागर में यदि चीनी नौसैन्य क्षमता का विकास रुकेगा नही तो इसमें देर जरूर होगी।

कहना है कि 20 साल की यह छात्रा सिर में लगी चोट और स्कूल में पढ़ाई को लेकर बने काफी दबाव की वजह से आत्महत्या को मजबूर हो गई। शिनहुआ ने गांसू प्रांत के स्थानीय अधिकारियों के हवाले से कहा है कि सेरिंग की नाम की यह युवती एक रेडिएटर से सिर टकरा जाने से लगी चोट की वजह से अस्पताल में भर्ती थी और आत्मदाह करने से पहले कई बार बेहोश भी हो चुकी थी। शिनहुआ का कहना है कि "उसका स्कूल में ग्रेड घटने लगा था, जिसकी वजह से उस पर काफी दबाव था और उसका पढ़ाई एवं जीवन के प्रति उत्साह खत्म हो गया था।" चीन ने कुछ आत्मदाह की पुष्टि की है, लेकिन करीब 25 आत्मदाह की बात नहीं स्वीकार रहा जो विदेशी मीडिया और तिब्बत अधिकार संगठनों के मुताबिक पिछले एक साल में हुए है। अलग–अलग समूहों द्वारा आत्मदाह एवं मौतों के कई प्रतिस्पर्धी आंकड़े सामने आए हैं। सिचुआन पर शासन करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी समिति के सदस्य ली चांगपिंग ने कहा कि पिछले दो साल में सिचुआन प्रांत में करीब 20 लोगों ने खुद को आग लगाई है। ली ने हाल में अबा और सिचुआन प्रांत के गांजी प्रशासनिक क्षेत्र का दौरा किया है जहां कि आत्मदाह की ज्यादातर घटनाएं हुई हैं। इस तरह की घटनाएं कम होने का संकेत नहीं मिल रहा जबकि चीन ने सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी है और तिब्बती इलाकों को बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जिससे यह जानना असंभव सा हो गया है कि तिब्बत के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है। चीन यह आरोप लगाता रहा है कि निर्वासित तिब्बती बौद्ध नेता दलाई लामा के समर्थक आत्मदाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं और सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से पुलिस के हाथों अनगिनत तिब्बती मारे गए हैं। खबरों के अनुसार चीनी पुलिस अधिकारियों ने भारत में दलाई लामा (जिन पर चीन यह आरोप लगाता रहा है कि वे तिब्बत को शेष चीन से अलग करने का अभियान चला रहे हैं) से धार्मिक शिक्षण हासिल कर लौट रहे सैकड़ों तिब्बती नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जबरन पुनर्शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। दलाई लामा का कहना है कि वह केवल तिब्बत के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। चीन का कहना है कि वह तिब्बतियों जैसे सभी अल्पसंख्यक समूहों से उचित व्यवहार कर रहा है और उसने इन इलाकों में लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं।

यह तिब्बत और समूचे चीन के लिए काफी संवेदनशील समय है। चीन का वार्षिक विधायी सत्र सोमवार को ऐसे समय में शुरू हो रहा है, जबकि पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त हो चुकी है। मार्च इसलिए भी संवेदनशील महीना है क्योंकि इस माह तिब्बती कई महत्वपूर्ण वर्षगांठ मनाते हैं जिनमें 1959 की विफल जनक्रांति (जिससे दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी) और साल 2008 के सरकार विरोधी खूनी दंगे की वर्षगांठ, जिसने तिब्बत की राजधानी ल्हासा को हिलाकर रख दिया था। सीक्यांग के नेता भी उन हिंसक अलगाववादी आंदोलनों पर सख्ती से पेश आते हैं जो इस मध्य एशियाई सीमा क्षेत्र पर समय–समय पर उभर जाते हैं। इनका कहना है कि सीक्यांग के नंबर एक लक्ष्य (विकास) को हासिल करने के लिए स्थिरता पूर्व शर्त है और वे उन्हें कुचल देने को प्रतिबद्ध हैं जिन्हें क्षेत्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव झांग छुनजियान 'सड़े हुए अंडे और खराब तत्व' कहते हैं। सीक्यांग से आए प्रतिनिधिमंडल ने भी इस पर चर्चा की कि सरकार की नवीनतम नीतियों से किस तरह से रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इस बैठक के बाद पत्रकारों से झांग ने कहा, "जब भी कोई घटना होती है हम उसे दृढ़ता से कुचल डालते हैं। आगे भी यदि कोई घटना होगी तो हम उसे कुचल डालेंगे।"

क्विंघई में विरोध प्रदर्शन करने वाले तिब्बतियों पर पुलिस गोलीबारी में एक की मौत, दो घायल

(एपी एवं एएफपी, 11 मार्च, बीजिंग एवं नई दिल्ली)

पश्चिमी चीन में चीनी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की घातक गोलीबारी में एक तिब्बती की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। एक आंदोलनकारी संगठन और एक रेडियो चैनल ने शनिवार को यह जानकारी दी। लंदन स्थित संगठन फ्री तिब्बत और रेडियो फ्री एशिया ने तिब्बत के अपुष्ट सूत्रों के हवाले से बताया है कि मंगलवार को पुलिस ने तीन लोगों पर गोली चला दी जो 25 जनवरी की एक घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। 25 जनवरी की इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने क्विंघई प्रांत के तिब्बती इलाके में एक पुलिस थाने में चीनी झंडे को फाड़ दिया था। हालांकि, गोलोगा प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित पेमा काउंटी के स्थानीय सरकारी विभाग और पुलिस थाने के कर्मचारियों ने फोन पर बताया कि उन्हें गोलीबारी की कोई आवाज सुनाई नहीं दी है। निर्वासित तिब्बती सरकार ने शनिवार को कहा कि अशांत तिब्बती इलाके में बीजिंग की 'कठोर नीति' एक विफलता है और उसने चीन के आगामी नेताओं से अनुरोध किया है कि वे तिब्बतियों को ज्यादा स्वायत्तता दें। करीब एक दशक बाद इस साल चीन में सबसे बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है जिससे इसके मौजूदा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रिटायर हो जाएंगे, इससे यह उम्मीद बनी है कि नया नेतृत्व तिब्बत के प्रति रवैए में नरमी लाएगा। निर्वासित सरकार के मुखिया लोबसांग सांगे ने कहा, "हमें उम्मीद है कि चीन के आगामी नेता वास्तविक बदलाव की शुरुआत करेंगे और वे यह स्वीकार करने की बुद्धिमत्ता दिखाएंगे कि तिब्बत में चीन सरकार की कठोर नीतियां विफल हो चुकी हैं।" सांगे का यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब दुनिया भर में तिब्बती 'जनक्रांति दिवस' मना रहे हैं। साल 1959 में इसी दिन चीनी शासन के खिलाफ तिब्बतियों की जनक्रांति विफल रहने के बाद दलाई लामा को भारत में शरण लेना पड़ा था। उन्होंने अपना यह बयान उत्तरी भारत के धर्मशाला शहर में स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के मुख्यालय से जारी किया। सांगे ने कहा, "तिब्बतियों का संघर्ष चीनी लोगों या चीन देश के खिलाफ नहीं है। यह चीन जनवादी गणराज्य की नीतियों के खिलाफ है। चीन को तिब्बत में समस्या की गहराई को समझना होगा और यह बात समझनी होगी कि इन समस्याओं को हिंसा के द्वारा नहीं सुलझाया जा

सकता।" सांग ने चीन से अनुरोध किया कि वह तिब्बतियों के 'मध्यम मार्ग नीति' को स्वीकार करें जिसमें चीनी संविधान के ढांचे के भीतर ही तिब्बतियों के लिए 'वास्तविक' स्वायत्तता देने की बात की गई है।

पिछले एक साल में विरोध प्रदर्शनों में करीब दो दर्जन तिब्बतियों ने खुद को आग लगा लिया है। तिब्बती आंदोलनकारियों का कहना है कि चीन द्वारा तिब्बती धर्म एवं संस्कृति के दमन का विरोध करते हुए इन लोगों ने आत्मदाह किया है। दूसरी तरफ, चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने दलाई लामा के समर्थकों पर आरोप लगाया है कि वे आत्मदाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं। फ्री तिब्बत का कहना है कि इस हफ्ते मारे गए व्यक्ति की पहचान छोएरी के रूप में हुई है। इनके साथ ही दो व्यक्तियों को तब पुलिस ने गोली मार दी जब वे एक व्यक्ति थबवांग की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए थाने पर गए थे। थबवांग ने संभवतः एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। रेडियो फ्री एशिया ने बताया कि जब ये तीनों लोग थुबवांग को पुलिस से बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर गोली चला दी गई। फ्री तिब्बत ने बताया कि घायल दोनों व्यक्ति सगे भाई हैं और उनकी पहचान कारखो और जामफेल लोदोरे के रूप में हुई है। एक को बांह में और दूसरे को पैर में गोली लगी है। बीजिंग की एक प्रख्यात लेखिका सहित कई तिब्बतियों ने आत्मदाह के इस सिलसिले को बंद करने की वकालत की है। उनका कहना है कि इससे तिब्बतियों के अधिकार की लड़ाई में कोई मदद नहीं मिल रही। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के अनुसार शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने बीजिंग में विधायी संस्थाओं के तिब्बती प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वे स्थिरता बनाए रखें, नस्लीय एकता का संदेश प्रसारित करें और मातृभूमि की एकता की रक्षा करें। दलाई लामा ने आत्मदाह करने वाले लोगों के साहस की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि तिब्बत में चीन द्वारा 'सांस्कृतिक नरसंहार' की वजह से ऐसा अतिवादी विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

चीन के प्रति रणनीति में होना चाहिए सतर्क संतुलन

(रेडिफ डॉट कॉम, 1 मार्च) नई दिल्ली में मंगलवार को "नॉनअलाइमेंट 2.0– अ फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर इंडिया इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी" (गुटनिरपेक्ष 2.0: 21वीं सदी में भारत के लिए विदेशी एवं सामरिक नीति) शीर्षक का एक दस्तावेज जारी किया गया। यह दस्तावेज सुनील खिलनानी, राजीव कुमार, प्रताप भानु मेहता, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) प्रकाश मेनन, नंदन नीलेकणि, श्रीनाथ राघवन, श्याम शरण और सिद्धार्थ वरदराजन का संयुक्त विचार–विमर्श है। समूह के इस विचार–विमर्श को नेशनल डीफेंस कॉलेज और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली का भी प्रशासनिक सहयोग मिला है। इस दस्तावेज के एक अध्याय 'एशियन थिएटर' में चीन के बारे में कई टिप्पणियां की गई हैं और कहा गया है कि भारत की चीन के प्रति रणनीति में सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा, आर्थिक एवं राजनीतिक हित, द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय संदर्भ के बीच सतर्क संतुलन होना चाहिए। दस्तावेज में कहा गया है कि चीन निकट भविष्य में भारत की विदेश नीति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना रहेगा। यह ऐसी बड़ी ताकत है जो भारत के भू–राजनीतिक क्षेत्र पर सीधा अतिक्रमण करता है। जैसे–जैसे चीन की आर्थिक एवं सैन्य क्षमता विस्तृत होती जाएगी, भारत के मुकाबले उसकी ताकत का अंतर और बढ़ता जाएगा। जैसा कि यह सबको पता है कि भारत एवं चीन के बीच एक परस्पर स्वीकार्य सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई बार झड़प या अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं। हमारी रणनीति यह होनी चाहिए कि उत्तर में चीन–भारत सीमा पर 'रेखा से बंधा' रहा जाए और यदि संभव हो तो दक्षिण में समुद्री क्षेत्र में अपने प्रभाव का और विस्तार किया जाए।

सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास कार्य तेज करने की जरूरत

इस रणनीति पर इस लिहाज से काम करने की जरूरत है कि भू सीमा पर चीनी प्रतिरक्षा क्षमता हमेशा बेहतर है और निकट भविष्य में सीमा विवाद हल होते नहीं दिख रहा। यह देखते हुए कि चीन ने दूसरे छोटे पड़ोसियों के साथ कई सीमा संबंधी मसले सुलझा लिए हैं (कम से कम कुछ समय के लिए) अब भारतीय सीमा विवाद को वह काफी प्रमुखता से उठा सकता है। यह काफी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के अपने पिछले दौरे पर चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने कहा था कि सीमा संबंधी मसलों को हल करने में काफी समय लगेगा। यह चीन की पहले की नीति से उलट है जिसमें कहा गया था कि विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के द्वारा इस मसले पर एक राजनीतिक समाधान निकालने की कोशिश की जा सकती है, इस बात का फायदा उठाते हुए कि दोनों देशों के बीच रिश्ता अब एक सामरिक और वैश्विक पहलू हासिल कर चुका है। इसके अनुसार सीमा विवाद का हल जल्द निकालना संभव भी था और जरूरी भी। लेकिन अब इस नीति में काफी बदलाव आ चुका है। यह महत्वपूर्ण है कि अपनी सैन्य क्षमताओं और उनकी तैनाती में असममिति को दूर करने के लिए हम अपनी सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में सुधार कार्य तेज करें (खासकर आवास एवं आपूर्ति पंक्ति के लिहाज से)। इसके साथ ही हमें संचालनात्मक धारणाओं और क्षमताओं का विकास भी करना चाहिए ताकि चीन किसी बड़े अतिक्रमण का दुस्साहस न कर सके।

चीन का फंसे रहना भारत के हित में

फिलहाल समुद्री क्षमताओं के मामले में भारत कई मायनों में चीन से आगे है, लेकिन अब इस मामले में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन का मुख्य रूप से ध्यान अब इस बात पर है कि पीला सागर, ताइवान जलडमरूमध्य,पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर पर प्रभुत्व कैसे कायम हो। हिंद महासागर उसकी इस प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर है। लेकिन यह भारत के हित में है कि चीन समुद्री मंच पर अपनी पहली प्राथमिकता में ज्यादा से ज्यादा फंसा रहे। एशिया–प्रशांत के मंच पर अमेरिकी नौसैनिकों की भारी तैनाती बने रहना, जापानी नौसैनिकों की ज्यादा सक्रिय

चीन को इस बात के लिए मनाने से कि वह दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती समुदाय के साथ सामंजस्य बनाकर रहे, वास्तव में भारत–चीन के बीच तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके लिए शुरूआती बातचीत काफी चौकस तरीके से करनी होगी।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आंख

1 आमदो के रेबकांग मठ में 38 साल के जामयांग पालदेन ने आत्मदाह कर लि
2 पूर्वी तिब्बत के नाबा में 16 मार्च को आत्मदाह कर लेने वाले 20 साल के भिक्षु
3 चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ के भारत दौरे से पहले विरोध प्रदर्शन में आत्मदाह
4 चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ के दौरे से पहले नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौ
5 तेनपा दार्गे (फाइल फोटो)
6 तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों के प्रति एकजुटता दिखाने और चीनी पुलिस द्वा
10 मार्च को तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति की 53वीं वर्षगांठ पर अपने सिर मुड़ाते
7 छिमे पालदेन (फाइल फोटो)
8 धर्मशाला में 30 मार्च को राजकीय सम्मान के साथ जामफेल येशी को दिए जा
में लपेटकर रखा गया उनका शव।
9 पूर्वी तिब्बत में रेबकोंग के डोलमा चौक पर गत 17 मार्च को 'खाता' से ढका सोन
जुटे हैं।
10 तिब्बत में आज़ादी और परमपावन दलाई लामा को वापस बुलाने की मांग को

(9)

(8)

(3)

(4)

कैमरे की आंख से

ने आत्मदाह कर लिया।
ले 20 साल के भिक्षु लोबसांग सुल्त्रिम।
प्रदर्शन में आत्मदाह कर लेने वाले 27 साल के निर्वासित तिब्बती जामफेल येशी।
एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का–मुक्की करते निर्वासित तिब्बती।

और चीनी पुलिस द्वारा हाल में किए गए दमन पर चिंता जाहिर करने के लिए धर्मशाला में
र अपने सिर मुड़ाते तिब्बती विद्यार्थी।

येशी को दिए जा रहे अंत्येष्टि के दौरान सुग–ला खांग के प्रांगण में तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज

'खाता' से ढका सोनम धार्गे का जलकर काला हो चुका शव। इस अवसर पर हजारों तिब्बती

बुलाने की मांग को लेकर माल्हो में 18 मार्च को करीब 2000 तिब्बतियों ने प्रदर्शन किया।

(5)

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(7)

(6)

हाल में तिब्बत से भागकर आने वाले घुमंतू नस्ल के 20 साल के युवक शेराब ग्यात्सो ने कहा, "मैं भारत में आज़ादी का अनुभव कर रहा हूं।"कोलंबिया विश्विविद्यालय के रॉबर्ट बर्नेट का कहना है कि तिब्बती भारत में मिलने वाली अपनी मेजबानी के खत्म होने का जोखिम नहीं उठा सकते।

और सबल मौजूदगी और इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया एवं वियतनाम जैसे प्रमुख समुद्र तटवर्ती देशों द्वारा नौसैन्य क्षमता का विकास, इन सबसे हिंद महासागर में यदि चीनी नौसैन्य क्षमता का विकास रुकेगा नही तो इसमें देर जरूर होगी। हमें इस अवसर का फायदा उठाते हुए अपनी नौसैनिक क्षमताओं का विकास करना चाहिए।हमारी क्षेत्रीय कूटनीति इस रवैए का समर्थन करने वाली होनी चाहिए जिसके लिए हमें इन पलड़े को बराबर करने वाली ताकतों से गहरा संबंध विकसित करना चाहिए। इसके तहत ऐसे देशों से सुरक्षा सहयोग का नेटवर्क बनाया जा सकता है और नियमित नौसैनिक अभ्यास किए जा सकते हैं।

भारत को क्यों करना चाहिए अपनी तिब्बत नीति का पुनर्आकलन

राजनीतिक पक्ष में देखें तो भारत को चीन के प्रति अपना रवैया काफी सावधानी से पेश करना चाहिए और इसमें बदलते वैश्विक एवं पर्यावरण विकास के आधार पर लगातार बदलाव किया जाना चाहिए। भारत के प्रति चीनी खतरे के बोध में स्थानीय और वैश्विक, दोनों तरह के पहलू हैं। स्थानीय पहलू तिब्बत को शामिल करता है। हमारी तिब्बत नीति पर पुनर्आकलन होना चाहिए और इसे नए सिरे से समायोजित किया जाना चाहिए। चीन को इस बात के लिए मनाने से कि वह दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती समुदाय के साथ सामंजस्य बनाकर रहे, वास्तव में भारत–चीन के बीच तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके लिए शुरुआती बातचीत काफी चौकस तरीके से करनी होगी। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसका शत्रुतापूर्ण जवाब मिलने का भी जोखिम है, खासकर चीन की जनमुक्ति सेना के कट्टरपंथी हलकों से। लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित निर्वासित तिब्बती सरकार को राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण के बाद तिब्बत की स्थिति और जटिल हो गई है। चीन यह सोचता है कि तिब्बती समुदाय दलाई लामा के चयन का अपना परंपरागत तरीका जारी रखेगा, जबकि खुद चीन इसको अपने वश में करना चाहता है। अपने समुदाय के लोगों के बीच दलाई लामा की लोकप्रिय वैधानिकता एक ऐसा तथ्य है जिसे चीन को स्वीकार करना होगा।

चीनी खतरे के बोध को करना होगा नजरअंदाजः

वैश्विक मंच पर देखें तो भारत को चीन एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे 'लहराते देश' के रूप में देखता है जिसका चीन के संभावित दुश्मनों के साथ जुड़ाव उसके लिए गतिरोध पैदा कर सकता है। भारतीय कूटनीति के सामने चुनौती यह है कि कई बड़ी ताकतों के साथ संबंधों का ऐसा व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाए जिससे चीन को इस बात के लिए मजबूर किया जा सके कि भारत के साथ निपटने में वह संयम बरते। इसके साथ ही हमें रिश्तों को ऐसे मोड़ पर ले जाने से परहेज करना होगा जिसमें वह भारत को खतरा समझने लगे। इसके लिए हमें राजनयिक और सैन्य दोनों माध्यमों से बारीकी से संचालित एवं समन्वित विदेश नीति की जरूरत होगी। यदि चीन भारत को ऐसे देश के रूप में देखता है जो अटल रूप से चीन को एक दायरे में सीमित रखने वाले विरोधी खेमे में रहने को प्रतिबद्ध है तो वह खुले तौर पर भारत के प्रति काफी शत्रुतापूर्ण और नकारात्मक नीतियां अपना सकता है, बजाय इसके कि भारत को एक ज्यादा स्वतंत्र रास्ते पर चलने को प्रेरित करते रहा जाए।

भारत–चीन के आर्थिक संबंध एक जटिल और कुछ हद तक अस्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन असमान तौर पर जिसमें लगातार बढ़ता व्यापार अधिशेष चीन के पक्ष में है। हम इसे रोकने के लिए अपने बाजार में चीनी पहुंच को सीमित करने का प्रयास कर सकते हैं, खासतौर से अपने बुनियादी ढांचा बाजार में। या हम चीन को अपने बाजार में पहुंच की इजाजत कई शर्तों के साथ दे सकते हैं जिससे अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय हितों की रक्षा हो और उनको बढ़ावा मिले। इस बात को देखते हुए कि भारतीय बुनियादी ढांचा बाजार अगले कुछ सालों में एक लाख करोड़ डॉलर के दायरे में पहुंच सकता है, निश्चित रूप से चीन इसमें अपनी पहुंच बढ़ाने का काफी इच्छुक है। हम चीन की इस रुचि का फायदा उठाते हुए दूसरे क्षेत्रों में अपने अनुकूल परिणाम हासिल कर सकते हैं जैसे कि ऐसी राजनीतिक रियायतें हासिल करना जो भारत के हित में हों।

भारत को अपनी मोल–तोल की ताकत को ज्यादा नहीं आंकना चाहिए

चीन के साथ हमारे आर्थिक रिश्तों में सबसे बड़ी चिंता वहां के सरकारी उद्यमों की दखल है। चीन के बैंक अक्सर चीनी कंपनियों को तरजीही तौर पर कर्ज देते हैं क्योंकि उनका आकार काफी बड़ा है और वे पूरी तरह बाजार की ताकतों से संचालित नहीं होते। चीन की कई प्रमुख विनिर्माण कंपनियां भी सार्वजनिक उद्यम हैं और उन्हें भी ऐसे सरकारी बैंकों के कर्ज आसानी से मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब चीनी कंपनियां किसी खुले टेंडर में प्रतिस्पर्धी बोली लगाती हैं तो वे अन्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भारी पड़ती हैं और मजबूत बोली (कम से कम रकम की) लगाने में सक्षम होती हैं। हालांकि, हमारे देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को जिस तरह की पूंजी की जरूरत हैं उसे देखते हुए इस तरह का तरजीही कर्ज वास्तव में काफी उपयोगी हो सकता है। इसलिए इस बारे में कई सवालों पर गौर करना होगा। भारत ऐसे मसलों का समाधान व्यवस्थित रूप से किस तरह करता है यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक और अतिरिक्त समस्या सॉफ्टवेयर के माध्यम से जासूसी और खुफिया सूचनाएं जुटाने की भी है जिसका साक्ष्य चीनी दूरसंचार उपकरणों पर लगे प्रतिबंधों से मिलता है।

आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों में असममिति को देखते हुए हमें अपनी मोलतोल की ताकत को आवश्यकता से ज्यादा नहीं आकना चाहिए। बड़े ऑर्डर को आर्थिक एवं व्यापारिक रियायतों से जोड़ना ज्यादा व्यावहारिक होगा, जिनमें भारत आधारित कारखानों आदि में निश्चित निवेश को भी शामिल किया जा सकता है। यह उम्मीद करना भी मुनासिब होगा कि बढ़ती आर्थिक आज़ादी से राजनीतिक संबंध ज्यादा प्रबंधनीय हो सकते हैं और उसमें उतार–चढ़ाव कम आते हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ता व्यापार अधिशेष वास्तव में अपनी मात्रा और संघटन दोनों के लिहाज से चिंता का

विषय है। भारतीय उद्योग की चीनी आयात पर निर्भरता न केवल मात्रा के लिहाज से बढ़ रही है बल्कि ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन को भारत से मुख्यतः निर्यात प्राकृतिक संसाधनों का हो रहा है, जबकि वहां से आयात मुख्यतः ऊंचे स्तर के विनिर्मित वस्तुओं का हो रहा है। भारत को अपने विशाल सेवा क्षेत्र को देखते हुए चीन में ज्यादा बाजार पहुंच और उपस्थिति पर जोर देना चाहिए और व्यापार असुंतलन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के बीच सतर्क सुंतलन

एक क्षेत्र जहां चीन से भारत प्रभावी तरीके से मोलतोल कर सकता है वह है तकनीकी हस्तांतरण का क्षेत्र। अपने बाजार में पहुंच देने के बदले उन्नत प्रौद्योगिकी हासिल करने और इसके साथ ही घरेलू तकनीक विकसित करने की क्षमता का भारत ने अभी तक उस तरह प्रभावी रूप से इस्तेमाल नहीं किया है जिसकी जरूरत है, खासकर विकसित देशों के साथ। उदाहरण के लिए जब एक विमानन कंपनी जैसे कि इंडिगो विदेशी कंपनी एयरबस के साथ 16 अरब डॉलर (करीब 83,200 करोड़ रुपए) का सौदा करती है तो इस सौदे की शर्तों में तकनीक हस्तांतरण को भी शामिल करना चाहिए। यहां तक कि भारत के प्रतिरक्षा सौदे भी तकनीकी हस्तांरण की शर्तों के मामले में निराश करते हैं और घरेलू स्तर से बेहद कम मूल्य वर्धित गतिविधियों की ही आपूर्ति की जाती है। चीन यह प्रबंधन करने में अच्छी तरह से सफल रहा है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वहां की सरकार विभिन्न कंपनियों (जिनमें ज्यादातर सार्वजनिक कंपनियां हैं) के कार्यों का समन्वय करने में सफल रही है, जबकि भारत के पास यह सुविधा नहीं है। वास्तव में अन्य विकसित देशों के मुकाबले चीन के साथ तकनीक हस्तांतरण सौदों पर बातचीत करना आसान है क्योंकि विकसित देश अपनी बौद्धिक संपदा के हक पर ज्यादा जोर देते हैं। हाल में चीन की एक दूरसंचार कंपनी ने बंगलुरु में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है ताकि वह भारत सरकार को इस बात के लिए सुनिश्चित कर सके कि उसके द्वारा आयातित उपकरणों में बातचीत सुनने की किसी प्रकार की गुप्त रिकॉर्डिंग तकनीक नहीं होती है। भारत की चीन रणनीति में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय संदर्भों का सचेत संतुलन बनाना होगा। भारत एवं चीन की क्षमताओं में मौजूदा एवं भविष्य की असममितियों को देखते हुए यह अनिवार्य है कि हम यही सही संतुलन हासिल करें। यह शायद अगले सालों में भारतीय रणनीति के लिए एकमात्र सबसे बड़ी चुनौती होगी।

(नेशनल डीफेंस कॉलेज और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली से साभार)

भारत का तिब्बत कार्ड

(हिंदुस्तान टाइम्स, 3 मार्च, 2012) भारत ने एक चीन नीति की पुष्टि करते हुए कहा है कि उसकी जमीन पर होने वाली चीन विरोधी गतिविधियां गैरकानूनी हैं। साल 2008 में चीन इस बात के लिए कृतज्ञ हुआ था कि भारत ने तिब्बती आंदोलनकारियों को बीजिंग ओलंपिक टॉर्च रीले में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने से रोका था। भारत ने द्विपक्षीय संबंधों में तब तक तिब्बत कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया था जब तक चीन ने जम्मू–कश्मीर के नागरिकों को नत्थी वीजा देने की शुरुआत नहीं की थी। इस तरह का वीजा देने के बाद भारत ने तिब्बत की कश्मीर से तुलना करते हुए कहा था कि चीन यदि यह चाहता है कि तिब्बत पर उसकी चिंताओं पर गौर किया जाए तो उसे बदले में कश्मीर पर भारत की प्रभुसत्ता के मामले में भी 'पारस्परिक संवेदनशीलता' दिखानी होगी। साल 2010 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के भारत में दौरे की समाप्ति पर जो संयुक्त बयान जारी किया गया था उसमें भारत ने एक चीन नीति पर जोर नहीं दिया था। भारत अब चीन और दलाई लामा के अनुयायिओं के झगड़े में गहराई से उलझता जा रहा है। हाल में, चीन ने भारत के साथ दिल्ली में होने वाली सीमा वार्ता को इसलिए टाल दिया था क्योंकि उसी समय राजधानी में दलाई लामा को एक कार्यक्रम में संबोधित करना था। गत दिसंबर माह में बिहार के गया में आयोजित एक बौद्ध समागम में लौट रहे तिब्बतियों के तिब्बत वापसी पर गिरफ्तार किए जाने की खबरें हैं। लेकिन इससे तिब्बत से भाग कर आने वाले लोगों को भयभीत नहीं किया जा सका है। हाल में तिब्बत से भागकर आने वाले घुमंतू नस्ल के 20 साल के युवक शेराब ग्यात्सो ने कहा, "मैं भारत में आज़ादी का अनुभव कर रहा हूं।"कोलंबिया विश्वविद्यालय के रॉबर्ट बर्नेट का कहना है कि तिब्बती भारत में मिलने वाली अपनी मेजबानी के खत्म होने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन बौद्ध भिक्षु काफी चिंतित हैं। धर्मशाला स्थित कीर्ति मठ के लोबसांग केशी ने कहा, "दलाई लामा अपनी उम्र के सत्तर के दशक में हैं। तिब्बत का हर व्यक्ति उनका दर्शन करना चाहता है।" उन्होंने कहा कि यदि तिब्बत में इसी तरह का दमन जारी रहा तो वहां चल रहा शांतिपूर्ण तिब्बती आंदोलन हिंसक रूप ले सकता है। तिब्बत मामलों के जानकार दिब्येश आनंद कहते हैं, "आत्मदाह निर्वासित तिब्बतियों को उद्वेलित कर रहा है जो निस्संदेह दलाई लामा के मध्यम मार्ग नीति पर सवाल उठाएंगे जिसमें वास्तविक स्वायत्तता की मांग की गई है।

तब्बत में चीनी शासन के खिलाफ हुई एक जनक्रांति (जो विफल रही थी) की वर्षगांठ के अवसर पर न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने करीब 2000 लोगों का जबर्दस्त मार्च आयोजित किया गया।

हू की यात्रा से पहले तिब्बतियों को हिरासत में लिया गया

(नई दिल्ली, डेक्कन हेराल्ड, 1 मार्च) भारत ने चीन को भरोसा दिया है कि 'यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है कि नई दिल्ली मे 28 से 29 मार्च को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ के दौरे के दौरान किसी भी तरह की 'अप्रिय घटना' न होने पाए'। गुरुवार को यहां विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा और उनके चीनी समकक्ष यांग जिची के बीच हुई एक बैठक के दौरान ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान लॉजिस्टिक व्यवस्था पर चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्री ने इसके बाद उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की। पुलिस ने करीब एक दर्जन तिब्बतियों को हिरासत में लिया है जो

पुलिस कर्मियों ने इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने ले गए।

अन्य प्रदर्शनकारियों एवं मीडियाकर्मियों के सामने ही वह चीखते हुए दौड़ने लगा और कपड़े एवं त्वचा में आग लगने के बाद जमीन पर गिर पड़ा।

हैदराबाद हाउस के बाहर चीन विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, जहां कि कृष्णा और यांग के बीच वार्ता चल रही थी। अगले 28 एवं 29 मार्च को ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा हू जिनताओ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। हालांकि, गुरुवार को कृष्णा और यांग की मुलाकात के दौरान खास तौर से हू की यात्रा के दौरान 'तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ' निर्वासित तिब्बतियों द्वारा विरोध प्रदर्शन की चिंता नहीं हुई, लेकिन यह सुनिश्चित करने पर जरूर बात हुई कि 'ब्रिक्स सम्मेलन को बिना किसी अप्रिय घटना के सफल बनाया जाए।'यांग–कृष्णा की वार्ता स्थल के बाहर प्रदर्शन करने वाले तिब्बती चीन विरोधी नारे वाले तख्तियां लिए हुए थे और वे चीन के खिलाफ नारे लगा रहे थे जिसमें तिब्बत में भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के आत्मदाह को रेखांकित किया गया था। पुलिस कर्मियों ने इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने ले गए। इस दौरान तिब्बती लगातार तिब्बत में चीनी शासन खत्म करने के खिलाफ नारे लगाते रहे। यांग ने बाद में उप राष्ट्रपति अंसारी को बताया कि नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन को सफल बनाने के लिए चीन 'पूरा सहयोग' देने को तैयार है। नई दिल्ली में चीनी दूतावास द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यांग से बातचीत में कृष्णा ने कहा कि, "भारत आगामी ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी नेता का स्वागत करने के लिए उत्सुक है जो कि साझा वैश्विक एवं क्षेत्रीय हितों पर सदस्य देशों में परस्पर समझ एवं सहयोग बढ़ाने का एक उपयोगी मंच है।"

उत्तर–पूर्वी राज्यों में तिब्बत की आज़ादी के आंदोलन को तेज करेगा तिब्बती समूह

"यह दलाई लामा को तिब्बत में वापस बुलाने के लिए चीन की केंद्रीय सरकार पर दबाव बनाने का उनका अंतिम प्रयास है।"

(टीएनएन, 1 मार्च, गुवाहाटी) कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज उत्तर–पूर्वी राज्यों में जागरूकता अभियान को तेज करेगा ताकि तिब्बत पर चीनी प्रभुत्व के खिलाफ इस इलाके के लोगों को संगठित किया जा सके। तिब्बत में सैन्य, जनसांख्यिकीय एवं पर्यावरणीय बदलावों से चिंतित कोर ग्रुप आगामी 26 मार्च को गुवाहाटी में 'तिब्बत एवं हिमालयी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस सम्मेलन से पहले कोर कमेटी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक में इस बात के लिए योजना बनाई जाएगी कि तिब्बत में हाल में घटी घटनाओं की जानकारी लोगों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों तक कैसे पहुंचायी जाए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सांसद आर.के. खिमे और कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के उत्तर–पूर्व के संयोजक ने गुरुवार को उत्तर–पूर्व के लोगों से आह्वान किया कि वे तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ आंदोलन में शामिल हों। उन्होंने कहा, "उत्तर–पूर्वी भारत के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चीनी खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तिब्बत में हो रहे कई विकास कार्यों में चीन द्वारा यारलुंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम) नदी की दिशा मोड़ने का भारत पर काफी विनाशक असर होगा। पर्यावरणविदों के अनुसार तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के ऊपरी सिरे पर चीनी योजना की वजह से ही अरुणाचल प्रदेश के सियांग (ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल में नाम) नदी में जलस्तर घटता जा रहा है।"उत्तर–पूर्वी राज्यों में तिब्बत की 'आज़ादी' के आंदोलन को तेज करने की जरूरत पर जोर देते हुए खिमे ने कहा कि तिब्बत में जंगलों के विनाश का भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों पर विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया, "चीन सरकार द्वारा तिब्बत में खनिज संसाधनों का अनियोजित दोहन इस सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा होगा।" इस सम्मेलन में 26 मार्च को निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे के भी शामिल होने की उम्मीद है। खिमे ने बताया कि चीन सरकार के शासन में तिब्बती संस्कृति के क्षरण को लेकर भारत में रहने वाले दो लाख से भी ज्यादा तिब्बती शरणार्थी चिंतित हैं। अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए कोर ग्रुप ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को लेकर ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए। पर्यावरणविद सौम्यदीप दत्ता ने कहा कि यदि चीन यारलुंग सांगपो को पूर्वी चीन की ओर मोड़ देगा तो उत्तर–पूर्व, खासकर असम घाटी के लोगों को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।

तिब्बत जनक्रांति के अवसर पर न्यूयॉर्क में 2000 लोगों का मार्च

(एएफपी, 11 मार्च, न्यूयॉर्क) तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ हुई एक जनक्रांति (जो विफल रही थी) की वर्षगांठ के अवसर पर न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने करीब 2000 लोगों का जबर्दस्त मार्च आयोजित किया गया। तिब्बतियों के खिलाफ चीनी रवैए की भर्त्सना के साथ यह प्रदर्शन ब्रूकलिन ब्रिज से शुरू हुआ और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की तरफ बढ़ा। हिरासत में लिए गए वृत्त चित्र निर्माता धोनडुप वांगछेन की पत्नी ल्हामो सो ने भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी मातृभूमि में विरोध प्रदर्शनकारियों द्वारा शुरू हुए आत्मदाह के सिलसिले की वजह चीनी शासन ही है। इसके पहले शनिवार को भारत स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार ने भी आरोप लगाया था कि तिब्बत में आत्मदाह की लहर शुरू होने की वजह चीन के 'कठोर नीति' वाले नेता ही हैं। पिछले एक साल में 20 से भी ज्यादा तिब्बतियों ने (जिनमें से ज्यादातर भिक्षु हैं) बीजिंग शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए खुद को आग लगा लिया है। इसकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में काफी निंदा हुई है और आलोचकों ने इसके लिए चीन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक दमन को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ, चीन यह आरोप लगाता है कि दलाई लामा तिब्बत को शेष चीन से अलग करने के दांव के रूप में आत्मदाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

तिब्बत जागरूकता कार्यक्रम में भारतीय युवा भाामिल हुए

(तिब्बत डॉट नेट, धर्मशाला) नई दिल्ली स्थित भारत–तिब्बत समन्वय केंद्र ने गत 14 से 18 मार्च तक धर्मशाला में भारत तिब्बत समर्थक समूह (टीएसजी) युवा प्रशिक्षण एवं अभियान

कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के समन्वयकों ने तिब्बतनेट को बताया कि इसका उद्देश्य भारत में टीएसजी के आंदोलन को मजबूत करना और निर्वासन में स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। समूचे भारत से भारत–तिब्बत मैत्री समाज (आईटीएफएस), भारत–तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम), स्टुडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत (एसएफटी), हिमालयन कमिटी फॉर एक्शन ऑन तिब्बत (एचआईएमसीएटी), अंतरराष्ट्रीय भारत–तिब्बत सहयोग समिति (एबीटीएसएस), नेशनल कैंपेन फॉर फ्री तिब्बत सपोर्ट (एनसीएफटीएस) से जुड़े पूरे देश के करीब 16 युवाओं ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। चार दिन की इस कार्यशाला में छात्रों ने तिब्बती प्रशासन के अधिकारियों, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधियों और विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के लोगों से चर्चा की। सीटीए की तिब्बत नीति संस्थान के निदेशक श्री थुबटेन सामफेल ने कार्यशाला में शामिल लोगों को तिब्बत मसले को हल करने के लिए प्रस्तावित मध्यम मार्ग नीति की प्रकृति, विकास और उपलब्धियों के बारे में बताया। सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री टाशी ने साल 1960 में स्थापित हुए निर्वासित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सांगठनिक ढांचे के बारे में बताया। कशाग सचिवालय में उप सचिव श्री तेनजिन लेक्शे ने तिब्बत आज़ादी आंदोलन और तिब्बत समर्थक समूहों को पूरे भारत में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किन अवसरों का दोहन करना चाहिए इसके बारे में एक स्वॉट (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण किया। इसके अलावा कार्यशाला में शामिल युवाओं ने तिब्बती स्वयंसेवी संस्थाओं की मीडिया तक पहुंच और उनकी गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की। कार्यशाला में शामिल लोगों को तिब्बत के ज्वलंत मसलों की भी जानकारी दी गई जैसे प्राकृतिक पर्यावरण एवं खनिज संसाधनों का दोहन और वहां जारी मानवाधिकारों का उल्लंघन। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह से भारत में तिब्बत समर्थक समूहों के आंदोलन को गतिशील और मजबूत किया जाए खासकर जमीनी स्तर पर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तिब्बत समस्या का स्थायी हल भारत की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों की बढ़ती संख्या और उत्तर भारतीय राज्यों जम्मू–कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की घटनाएं भारत सरकार और भारतीय जनता के लिए भारी चिंता और खतरे की बात है। कार्यशाला में शामिल युवाओं ने तिब्बतन चिल्ड्रेंस विलेज, लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स, तिब्बत म्यूजियम और तिब्बती चिकित्सा एवं ज्योतिष संस्थान का दौरा किया। उन्होंने तिब्बती संसद के बजट सत्र की सीधे कार्यवाही भी देखी। कार्यक्रम का समन्वयन करने वाले तेनजिन पालजोर और टाशी नोर्बू ने तिब्बतनेट को बताया, "कार्यक्रम में शामिल सभी युवाओं ने वक्ताओं के साथ सक्रिय संवाद किया और भारत में क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के तरीकों पर चर्चा की। हम इस तिब्बत जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी भागीदारों को धन्यवाद देते हैं।

आत्मदाह करने वाले तिब्बती प्रदर्शनकारी की मौत

चीनी नेता के भारत दौरे के विरोध में आत्मदाह कर लेने वाले निर्वासित तिब्बती की बुधवार को मौत हो गई

(टेलीग्राफ, 28 मार्च, नई दिल्ली) सोमवार को नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान आत्मदाह कर लेने वाले 27 साल के जामफेल येशी की मौत हो गई है। अन्य प्रदर्शनकारियों एवं मीडियाकर्मियों के सामने ही वह चीखते हुए दौड़ने लगा और कपड़े एवं त्वचा में आग लगने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता धोनढुप ल्हडार ने कहा, "शहीद जामफेल येशी के बलिदान को हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उनका यह बलिदान तिब्बत की आगामी पीढ़ियों को भी प्रेरणा और प्रोत्साहन देता रहेगा।" गौरतलब है कि चीन के तिब्बती इलाकों में सख्त चीनी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पिछले एक साल में ही करीब 30 तिब्बती लोगों ने खुद को आग लगा लिया है। आत्मदाह कर लेने वाले लोगों का कहना था कि तिब्बत इलाकों में चीनी दमन इतना बढ़ चुका है कि तिब्बती लोगों के सामने अपना विरोध जताने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। गत मंगलवार को अमेरिकी सीनेट की समिति ने एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित कर आत्मदाह में मरने वालों के लिए शोक जताया और चीन से यह अनुरोध किया कि वह तिब्बतियों को लक्ष्य बनाकर चलाई जा रही दमनकारी नीतियों को बंद करे। चीन ने तिब्बती बौद्ध आध्यात्मिक नेता दलाई लामा पर आरोप लगाया है कि वह आत्मदाह को बढ़ावा दे रहे हैं। दलाई लामा कई दशकों से भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। चीन ने विरोध के लिए आत्मदाह की इन घटनाओं को आतंकवाद की कार्रवाई बताया है।

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के एक अधिकारी ली जिआयोजुन ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में बुधवार को लिखे एक आलेख में कहा है, "यह दलाई लामा को तिब्बत में वापस बुलाने के लिए चीन की केंद्रीय सरकार पर दबाव बनाने का उनका अंतिम प्रयास है।"

तिब्बत में चीनी नेता पदमा छोलिंग का कहना है कि दलाई लामा और उनके अनुयायी उन सुविधाओं को बनाए रखना चाहते हैं जो उन्हें उस दौर में हासिल थीं जब तिब्बत में सामंती समाज था और वहां के ज्यादातर लोग दास थे जिनको कोई भी व्यक्तिगत अधिकार हासिल नहीं था। चीन ने बुधवार को तथाकथित दास उन्मूलन दिवस मनाया। इसी दिन साल 1958 में चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर नियंत्रण हासिल किया था और इसके बाद दलाई लामा को निर्वासन में जाना पड़ा था। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के अनुसार छोलिंग ने कहा, "दलाई लामा एवं उनका गुट चाहे जो तरकीब इस्तेमाल करे अलगाव का विरोध करने एवं देश की एकता की रक्षा करने की तिब्बती जनता की मजबूत आकांक्षा को बदला नहीं जा सकता।"चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ भारत, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के

पुलिस ने तिब्बती बस्तियों को घेर लिया है और लोगों को मेटल बैरिकेड से होकर ही गुजरने दिया जा रहा है। युवा तिब्बतियों के कहीं आने–जाने पर पूरी तरह से रोक है सिवाय चिकित्सा एवं कोर्ट संबंधी जरूरतों के। हालांकि, इसके लिए भी उनके साथ पुलिस के जवान को भेजा जा रहा है।

दमन के द्वारा चीन निस्संदेह तिब्बत पर नियंत्रण बनाए रख सकता है, लेकिन केवल दलाई लामा ही तिब्बतियों को चीनी शासन को स्वीकार करने के लिए राजी कर सकते हैं।

लिए बुधवार दोपहर को नई दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने बताया कि पुलिस एवं अन्य सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया गया है कि हू के राजधानी में रहने के दौरान तिब्बती लोगों की आवाजाही को सीमित किया जाए। पुलिस ने तिब्बती बस्तियों को घेर लिया है और लोगों को मेटल बैरिकेड से होकर ही गुजरने दिया जा रहा है। युवा तिब्बतियों के कहीं आने–जाने पर पूरी तरह से रोक है सिवाय चिकित्सा एवं कोर्ट संबंधी जरूरतों के। हालांकि, इसके लिए भी उनके साथ पुलिस के जवान को भेजा जा रहा है। मंगलवार की रात को सैकड़ों तिब्बती कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें कवि तेनजिन सुंडुए भी शामिल थे। तिब्बत के प्रमुख आंदोलनकारी सुंडुए ने चीनी नेताओं की यात्राओं के दौरान पहले कई बार ऊंचे स्तर का विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने तिब्बती महिला संघ की एक बैठक में अपना भाषण खत्म ही किया था कि उन्हें 'एहतियातन हिरासत' में ले लिया गया। भगत ने कहा, "ऐसे मौकों पर विरोध प्रदर्शन का उनका लंबा इतिहास रहा है।" तिब्बती आंदोलनकारियों ने पुलिस की इस सख्त कार्रवाई की निंदा की है। भारतीय बुद्धिजीवी राजीव वोरा ने एक बयान में कहा, "यह कार्रवाई गैरकानूनी है और यह पूरी तरह से चीनी दबाव के सामने समर्पण और हमारे राष्ट्रीय गौरव का समर्पण है।"

तिब्बती युवा कांग्रेस के तेनजिन छोक्यी ने बताया कि पुलिस की इस सख्ती के बावजूद बहुत से तिब्बती कार्यकर्ता पुलिस की घेरेबंदी को तोड़ने में सफल रहे और उन्होंने पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। बुधवार को करीब एक दर्जन लोगों को तब गिरफ्तार किया गया जब वे विरोध प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि निर्वासित तिब्बतियों के मुख्यालय धर्मशाला में 'शहीद' येशी के लिए एक विशाल शवयात्रा का आयोजन किया जाएगा।

तिब्बत की नदियों को उत्तर की ओर मोड़ रहा है चीन

अपने भाषण के अंत में उन्होंने हू की नई दिल्ली यात्रा पर कहा, "एक दैत्य भारत आ रहा है।"

(इंडिया टुडे, 2 मार्च, नई दिल्ली) चीन के समृद्ध उत्तरी क्षेत्रों में जल संसाधन सिमट रहे हैं और दक्षिण की ओर पर्याप्त अतिरिक्त जल भंडार उपलब्ध हैं जो कि बहकर नीचे भारत की ओर आते हैं, जिससे चीन ने विशाल दक्षिण–उत्तर जल हस्तांतरण परियोजनाएं शुरू की हैं। इस विशाल परियोजना के तहत अपनी विशाल जनसंख्या को फायदा पहुंचाने के लिए चीन ऐसे बांधों और नहरों का निर्माण कर रहा है जिससे उसके दक्षिणी क्षेत्रों से जलधाराओं को मोड़कर उत्तरी क्षेत्रों के लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। चीन की योजना ब्रह्मपुत्र पर 28 बांध बनाने की है। नवंबर, 2010 में चीन ने तिब्बत के जांगमू में ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाना शुरू किया है। इस 510 मेगावॉट परियोजना में जेनरेटर के पहले सेट साल 2014 से शुरू हो जाएंगे। उत्तरी और पश्चिमी चीन में जल की किल्लत बढ़ते जाने की वजह से चीन को तिब्बत की नदियों को दक्षिण की ओर मोड़ने का ख्याल आया है। तिब्बत की नदियों की दिशा मोड़ने का भारत पर सीधा असर होगा। यदि इस पर योजना के मुताबिक काम चलता रहा तो चीन के कई अन्य पड़ोसियों के साथ ही भारत सबसे बड़ा पीड़ित होगा। गौरतलब है कि जल भारत एवं चीन के बीच लंबे समय से विवाद की वजह रहा है। ब्रह्मपुत्र दुनिया में स्वतंत्र रूप से बहने वाली अंतिम कुछ नदियों में से बची है। समूचा उत्तर–पूर्वी भारत और बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र की धाराओं पर ही निर्भर है। साल 2010 में जब चीन ने अंतिम तौर पर ब्रह्मपुत्र पर जांगमू बांध बनाए जाने की पुष्टि की तो सूखे भविष्य को लेकर सबकी आशंका सच साबित हो गई। चीन अपने 62 अरब डॉलर की दक्षिण–उत्तर जल हस्तांतरण परियोजना को लेकर काफी उत्साहित दिखता है। इसका उद्देश्य दक्षिण चीन से उत्तर के शुष्क इलाके में स्थित येलो नदी की खाड़ी में हर साल 44.8 अरब क्यूबिक मीटर जल हस्तांतरित करने की है। कई दक्षिण–पूर्व एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में जल समझौते किए हैं, लेकिन चीन ने अब तक इन समझौतों से दूरी बनाए रखी है। इसकी जगह चीन अपने बांध निर्माण अभियान में मदमस्त है। यह एक ऐसी जल रणनीति है जो इसके पड़ोसी देशों में भरोसा बनाने में विफल रही है और कई विश्लेषकों ने तो इसे चीन की संसाधन हड़पने की जल आधिपत्य नीति करार दिया है।

बुद्ध और बाघिन

तिब्बत में आत्म–संहार बना अवज्ञा का नवीनतम तरीका *(बनियान, 10 मार्च, दि इकनॉमिस्ट)* एक प्रसिद्ध कहानी बताती है कि किस प्रकार अपने एक पूर्व जीवन में बुद्ध ने एक अत्यंत भूखी बाघिन पर दया किया था। यह बाघिन इतनी भूखी थी कि खुद के नवजात बच्चे को भी खा सकती थी, लेकिन उन्होंने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को बाघिन के हवाले कर दिया। इस कहानी को अक्सर उत्तरी भारत के धर्मशाला शहर में रहने वाले निर्वासित तिब्बती याद करते हैं क्योंकि वे अपने मातृभूमि में चल रहे आत्मदाह के अबाध सिलसिले से शोक संतप्त हैं। पिछले एक साल में कम से कम 26 तिब्बतियों ने आत्मदाह किया है जिसमें से ज्यादातर युवा बौद्ध भिक्षु हैं। मौत को गले लगा लेने वाली धधकती आग के बीच भी वे चीनी शासन के खिलाफ और दलाई लामा की वापसी का नारा लगाते रहे। दलाई लामा उनके आध्यात्मिक नेता हैं जो कि साल 1959 से ही धर्मशाला में रह रहे हैं। बाघिन की इस नीति कथा की सीख यह है कि वैसे तो बौद्ध धर्म अपने को नुकसान पहुंचाने वाली हिंसा से भी घृणा करता है, लेकिन यदि बलिदान व्यापक भलाई के लिए हो तो इसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है। लेकिन अत्यंत दुःखदायी सवाल यह है कि क्या बहादुरी के इन कार्यों से किसी का कोई भला हो रहा है। हालिया आत्मदाह की पहली लहर तब शुरू हुई जब 16 मार्च, 2011 को 20 साल के भिक्षु लोबसांग फुंसोग ने खुद को आग लगा लिया। समूचे तिब्बती पठार में तीन साल पहले फैले चीनी शासन के खिलाफ जनक्रांति की वर्षगांठ के अवसर पर फुंसोग ने यह कदम उठाया। तीन साल पहले यह अशांति भी असल में मार्च 1959 में हुए उस विफल विद्रोह की वर्षगांठ पर शुरू हुई थी जिसकी वजह से दलाई लामा को अपने

करीब 80,000 अनुयायियों के साथ भारत आना पड़ा था। हर साल अब इसकी वर्षगांठ कुछ और दुःखदायी खबरें लेकर आती है। इस महीने ही चार बच्चों की एक विधवा मां और एक किशोरी छात्रा आत्मदाह करने वाली पहली आम तिब्बती रही हैं। इस महीने ऐसी और भी घटनाएं होने की आशंका है। यदि इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य चीनी नीतियों में बदलाव करना है तो निराशाजनक रूप से इनका उलटा नतीजा ही हुआ है। न तो इनसे उन्हें विदेशी सरकारों के हाथ मरोड़ने से ज्यादा कुछ हासिल करने में सफलता मिली है और न ही इससे किसी ने धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार को मान्यता दी है। पिछले साल औपचारिक रूप से अपनी राजनीतिक भूमिका त्याग देने वाले दलाई लामा का काफी सम्मान है। लेकिन सम्मान की कोई सेना तो नहीं होती।

चीन में विरोध प्रदर्शनों से उदारीकरण को नहीं बल्कि नए सिरे से दमन को बढ़ावा मिल रहा है और यह केवल सिचुआन प्रांत के तिब्बती इलाके में ही नहीं हो रहा, जहां आत्मदाह का सिलसिला शुरू हुआ है।धर्मशाला में नए–नए तिब्बती लोगों के आने का सिलसिला जारी है जो विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार तिब्बत में चीनी सुरक्षा बलों की व्यापक रूप से मौजूदगी है, लोगों की आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध हैं, आंदोलनकारियों की तलाश में रात में छापामारी की जाती है और टेलीफोन एवं इंटरनेट तक छिटपुट पहुंच ही है। यह इलाका बाहरी दुनिया से इस कदर काट दिया गया है कि एक संगठन रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि तिब्बत से भी ज्यादा विदेशी पत्रकारों की मौजूदगी तो उत्तर कोरिया में है। धर्मशाला में हाल में आने वाले निर्वासित तिब्बतियों के लिए बना सुंदर स्वागत केंद्र इसी तरह की कहानी कहता है। हालांकि, करीब 500 लोगों के रहने लायक बने इस केंद्र में केवल दस फीसदी बिस्तर ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तिब्बत में साल 2008 में शुरू हुए दमन के बाद नेपाल के रास्ते भारत आने वाले निर्वासित तिब्बतियों की संख्या सालाना 3,000 से घटकर अब 1,000 से भी कम रह गई है। जो लोग आने में सफल होते हैं वे ऐसी कहानियां बताते हैं कि उनके परिवार ने उनके इस निर्वासन के लिए घूस देने की खातिर धन जुटाने के लिए भारी आर्थिक कुर्बानी दी है। इनमें से कई प्रवासी तिब्बती शिक्षा हासिल करने के लिए भारत आते हैं। पहले वे लौटने की योजना बनाकर आते थे, लेकिन अब ज्यादातर यह मानकर आते हैं कि उन्हें भारत में लंबे समय तक रहना होगा। जनवरी माह में चीन से आने वाले 7,000 से 8,000 तिब्बती उस विशाल समागम में शामिल थे जो बोधगया में दलाई लामा से शिक्षा हासिल करने के लिए जुटी थी। बोधगया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वे चीनी कागजात के साथ यात्रा करके आए थे। लेकिन लौटते समय इनमें से सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। नेपाल में रहने वाले करीब 20,000 तिब्बतियों का जीवन भी काफी कठिन हो गया है क्योंकि नेपाल सरकार चीन को खुश करने के लिए तिब्बती प्रदर्शनकारियों का दमन करती है। चीन इस महीने पड़ने वाली वर्षगांठ और इस हफ्ते बीजिंग में शुरु हुए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के वार्षिक सत्र के लिए तैयारी में लगा है तो अधिकारी तिब्बत में कठोर रुख अपनाने के लिए एक–दूसरे पर दोषारोपण का नाटक कर रहे हैं और आत्मदाह के लिए दलाई लामा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो इसे हतोत्साहित जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे खुलकर वर्जित नहीं किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के यूनाइटेड फ्रंट डिपार्टमेंट के झू वेइकुन (जिन्होंने दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बात करते समय चीनी दल का नेतृत्व किया था) ने अलग रवैया अपनाने का तर्क दिया है।पार्टी के अखबार में लिखे एक समाचारपत्र में उन्होंने सुझाव दिया है कि, "हमारी कुछ मौजूदा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीतियों की वजह से गैर इरादतन (राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों में) राष्ट्रवाद और चीनी राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हुई है।" इसके जवाब में वह सोचते हैं कि लोगों के पहचान पत्र पर बना नस्लीय अल्पसंख्यक का दर्जा हटा देना चाहिए और अल्पसंख्यकों के लिए अलग शिक्षा जैसी सुविधाएं खत्म की जानी चाहिए। निश्चित रूप से तिब्बती पहचान को अफसरशाही के जोर पर खत्म नहीं किया जा सकता। तिब्बतियों का कहना है कि आत्मदाह की इन घटनाओं को असंतोष प्रकट करने की निरर्थक कार्रवाई मानना गलत होगा। इसकी जगह वे इन घटनाओं को राष्ट्रीय एकता और उम्मीद के खिलाफ अवज्ञा के रूप में देखते हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार के एक अधिकारी अतिशा (जो कि समय–समय पर चीन से होने वाली निष्फल वार्ताओं में श्री झू के सामने बैठे थे) अब भी आशावादी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब 77 साल के हो चुके दलाई लामा ने 113 साल तक जीने का वादा किया है। श्री अतिशा को उम्मीद है कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन बहुत दिनों तक नहीं रहेगा और अंत में दलाई लामा वापस जाकर अपने जीवन के अंतिम दिन ल्हासा में गुजारेंगे।

दलाई लामा एकमात्र उम्मीद

हालांकि, अन्य लोग कम आशावादी हैं, उनको आशंका है कि तिब्बत में हान चीनियों के बसने से उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी मौजूदा दलाई लामा के जीवन से भी ज्यादा समय तक वहां टिकी रहेगी और खुद दलाई लामा का अवतार चुनने का प्रयास करेगी। वे पहले ही यह मान चुके हैं कि कुछ तिब्बती हार चुके हैं और उन्होंने चीनी शासन द्वारा मिलने वाले सब्सिडी और आर्थिक फायदों का बेहतरीन फायदा उठाने का निर्णय लिया है। हालांकि, उल्लेखनीय बात यह है कि तिब्बती इलाकों में 1959 के बाद की अब जो तीसरी पीढ़ी बड़ी हो रही है वह भी चीन से काफी घृणा करती है और दलाई लामा के प्रति निष्ठा रखती है। चीन इसे दूसरे तरीके से ही देखता है, लेकिन यह एक अवसर हो सकता है। अपने कई अनुयायिओं के विपरीत दलाई लामा ने तब तक चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार करने की बात मानी है जब तक उसे वास्तविक स्वायत्तता मिलती रहती है, साथ ही वह हिंसा का भी विरोध करते हैं। धर्मशाला में आने वाले तीन नए तिब्बती अपने नेता के दर्शन के लिए इंतजार में बैठे हैं। परंपरा के मुताबिक परमपावन नए आने वाले हर तिब्बती को दर्शन देते हैं। उनका कहना है कि परमपावन के दर्शन के बाद वह बिना किसी पछतावे के प्राण त्याग सकेंगे और वास्तव में उनकी

बाधिन की इस नीति कथा की सीख यह है कि वैसे तो बौद्ध धर्म अपने को नुकसान पहुंचाने वाली हिंसा से भी घृणा करता है, लेकिन यदि बलिदान व्यापक भलाई के लिए हो तो इसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है। लेकिन अत्यंत दुःख्दायी सवाल यह है कि क्या बहादुरी के इन कार्यों से किसी का कोई भला हो रहा है।

इस बात का मतलब भी है। दमन के द्वारा चीन निस्संदेह तिब्बत पर नियंत्रण बनाए रख सकता है, लेकिन केवल दलाई लामा ही तिब्बतियों को चीनी शासन को स्वीकार करने के लिए राजी कर सकते हैं।

चीनी वेबसाइट ने दलाई लामा पर 'नाज़ी' नीतियां अपनाने का आरोप लगाया

(सीएनएन–आईबीएन, 25 मार्च, नई दिल्ली) एक चीनी वेबसाइट ने दलाई लामा पर नाज़ियों जैसी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। वेबसाइट ने उन 30 तिब्बतियों की मौत के लिए भी दलाई लामा को जिम्मेदार ठहराया है जिन्होंने चीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आत्मदाह कर लिया है। चाइना तिब्बत ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रकाशित इस टिप्पणी को शनिवार को सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने भी जारी किया। यह चीन के तिब्बती इलाकों में विरोध प्रदर्शन की लहर शुरू होने के बाद की अब तक की चीन की सबसे सख्त प्रतिक्रियाओं में से है। गौरतलब है कि पिछले एक साल में करीब 30 तिब्बती भिक्षु, भिक्षुणी और आम लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए आत्मदाह कर चुके हैं। इन लोगों ने कथित रूप से उनके धर्म एवं संस्कृति के प्रति चीन सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ यह कदम उठाया है। इनमें कई ने दलाई लामा को वापस बुलाने के नारे लगाए थे।

इस टिप्पणी में चीन सरकार के अधिकारियों ने दलाई लामा पर और हमले भी किए हैं। दलाई लामा ने आत्मदाह करने वाले लोगों के साहस की तारीफ करते हुए कहा है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की वजह तिब्बत में चीन का 'सांस्कृतिक नरसंहार' है। हालांकि, वह हमेशा यह कहते रहे हैं कि विरोध प्रदर्शनों के इस चरम कदम को प्रोत्साहित नहीं करते क्योंकि इनसे और सख्त कदमों को आमंत्रण मिलता है। साल 2000 में शुरू हुए इस वेबसाइट में चीन सरकार के तिब्बत के बारे में दृष्टिकोण को पेश किया जाता है। वेबसाइट ने दलाई लामा पर आरोप लगाया है कि वह आत्मदाह को प्रेरित कर रहे हैं और नाज़ियों के नस्लीय अलगाव जैसे विचारों की वकालत कर रहे हैं। वेबसाइट का कहना है कि दलाई लामा ने लोगों को आत्मदाह करने के लिए प्रोत्साहित किया है क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था कि आत्मदाह करने वाले लोगों की याद में इस साल फरवरी में पड़ने वाले तिब्बती नव वर्ष लोसार का उत्सव न मनाया जाए। इस वेबसाइट की टिप्पणी के बारे में धर्मशाला स्थित दलाई लामा के कार्यालय की प्रतिक्रिया अभी नहीं मिल पाई है। लंदन स्थित संगठन फ्री तिब्बत ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर आत्मदाह की कई नवीनतम घटनाओं की जानकारी दी है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से इस माह की शुरुआत में 44 साल की एक महिला ने अपने शरीर पर केरोसीन से भिगोकर आत्मदाह कर लिया जिसमें उनकी मौत हो गई।

(एसोसिएटेड प्रेस से हासिल अतिरिक्त जानकारी के साथ)

'तिब्बत और हिमालय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी' पर सम्मेलन का आयोजन

(आईटीसीओ, गुवाहाटी 26 मार्च) गुवाहाटी में सोमवार को एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए निर्वासित तिब्बती सरकार की गृह मंत्री सुश्री ग्यारी डोलमा ने कहा कि तिब्बत चीन से भी ज्यादा भारत के करीब है। उन्होंने तिब्बत से सटे भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लोगों से आह्वान किया कि वे तिब्बत की आज़ादी के आंदोलन का समर्थन करें। सुश्री डोलमा ने कहा, "चीन सरकार जब तिब्बत के बारे में कुछ कहती है तो वह इसमें निश्चित रूप से अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल करती है। इसलिए यह हर भारतीय के हित में भी है कि वह तिब्बत में वास्तविक स्वायत्तता का समर्थन करे और मेरा मानना है कि उत्तर–पूर्व के लोग अपने साथ हमारी आवाज़ उठाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।" गुवाहाटी के विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज (नई दिल्ली) द्वारा 'तिब्बत और हिमालयी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी' विषय पर आयोजित सम्मेलन में निर्वासित तिब्बतियों, गुवाहाटी के स्थानीय लोगों और मीडिया कर्मियों के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। उत्तर भारत के धर्मशाला शहर में रहने वाली सुश्री डोलमा ने यह भी कहा कि चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ एक जलविज्ञान विशेषज्ञ हैं और चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांध बनाने की योजना के पीछे उनका ही दिमाग है। उन्होंने कहा, "केवल बांध ही नहीं, चीन सरकार तो अपनी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए विशाल नदियों की धारा को उत्तर की ओर मोड़ने की योजना बना रही है। इस तरह की परियोजनाएं यदि पूरी हुईं तो इनका भारत और बांग्लादेश के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर गंभीर नकारात्मक असर होगा।" अपने भाषण के अंत में उन्होंने हू की नई दिल्ली यात्रा पर कहा, "एक दैत्य भारत आ रहा है।" गौरतलब है कि चीनी राष्ट्रपति आगामी 28–29 मार्च को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं। इस सम्मेलन में उनके अलावा भारत, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिलेंगे।

इस सम्मेलन में अपने भाषण में श्री के.सी. अग्निहोत्री ने अरुणाचल प्रदेश के मसले पर अनावश्यक टांग अड़ाने और मैकमोहन रेखा पर चीनी रवैए के लिए भारत सरकार के 'कमजोर प्रतिक्रिया' की आलोचना की। अग्निहोत्री ने कहा, "मैकमोहन रेखा को शिमला समझौते से मान्यता दी गई थी और इस पर ब्रिटिश (भारत) सरकार एवं तिब्बत सरकार ने साल 1914 में हस्ताक्षर किए थे।हम भारत के लोग और निर्वासित तिब्बती अब भी मैकमोहन रेखा को आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर मानते हैं, लेकिन नई दिल्ली की केंद्र सरकार कई बार इसे विवादित सीमा के रूप में स्वीकार करती है जो कि वास्तव में चीन की भाषा है।"

असम के एक वरिष्ठ पत्रकार डी. एन. चक्रवर्ती ने तर्क दिया कि जितनी जल्दी संभव हो तिब्बत आज़ाद होना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से भी यह निवेदन किया कि वह तिब्बत को एक संप्रभु सरकार के रूप में मान्यता दे और उन्होंने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि वह निर्वासित तिब्बती सरकार को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे। चक्रवर्ती ने कहा, "तिब्बत पर चीन के लगातार कब्जे का विरोध करने के लिए हमें भारत में चीनी माल का बहिष्कार करना चाहिए। हमें यह बात समझनी चाहिए कि यह उत्तर–पूर्व में रहने वाले हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह तिब्बत आंदोलन का समर्थन करे। कोर ग्रुप फॉर तिब्बत कॉज के उत्तर–पूर्व के संयोजक श्री आर.के. खिमे ने 1962 के चीनी हमले और अरुणाचल पर कब्जे के बाद असम के तेजपुर में मार्च को याद किया। खिमे ने कहा, "भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब अमेरिका और फ्रांस से मदद मांगी और चीन सरकार को चेतावनी मिलने लगी तब कम्युनिस्ट चीन की फौजें भाग खड़ी हुईं। 1820 के बर्मा के हमले के बाद चीन के अलावा और किसी भी देश ने इस इलाके पर हमला नहीं किया था।"